सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 296 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, रविवार 09 अगस्त 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव, भारी बारिश व बिजली गिरने की चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बलरामपुर और बीजापुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में 1 जून से अब तक हुई मौसमी बारिश सामान्य से 7 फीसदी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल और उससे लगे उत्तर ओडिशा के ऊपर सिस्टम बना हुआ है। इसके असर से 9 अगस्त को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। शनिवार शाम रायपुर में झमाझम बारिश हुई। इसके बाद रात भर रुक-रुककर बारिश होती रही। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। इससे लोगों को आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

जिला अस्पताल में एल्डरमैन और सफाईकर्मी भिड़ीं

सक्ती। जिला अस्पताल परिसर में शनिवार को वार्ड क्रमांक 18 की नवनिर्वाचित महिला एल्डरमैन सुशीला गबेल और महिला सफाईकर्मी के बीच विवाद हो गया। सफाई व्यवस्था को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, सुशीला गबेल शनिवार को अपने निजी कार्य से जिला अस्पताल पहुंची थीं। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर उन्होंने वहां मौजूद महिला सफाईकर्मियों से सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई। इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख ने तलवार से काटा केक

रायपुर। छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार का तलवार से केक काटने का वीडियो वायलर हो रहा है। घटना रायपुर के टिटोस क्लब की है। धनंजय परिहार टिटोस क्लब के मालिक भी हैं। आरोप है कि इसी क्लब में रात 12 बजे के बाद भी पार्टी चलती रही और शराब परोसी जा रही थी। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लब के अंदर बड़ी संख्या में युवक-युवतियां मौजूद हैं। तेज म्यूजिक के बीच पार्टी चल रही है। इसी दौरान शिवसेना प्रमुख केक लेकर पहुंचते हैं और तलवार से केक काटते हैं। आसपास मौजूद लोग जश्न मनाते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं, वायरल वीडियो को लेकर शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। दोस्तों के कहने पर उन्होंने तलवार से केक काटा था।

नक्सलवाद खात्मे के बाद भी नहीं बदलेंगे छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में नियम

केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने रखा 'विरासत एवं प्रबल' श्रेणी में, 8 राज्यों के 25 जिले भी शामिल

श्रीकंचनपथ न्यूज

नईदिल्ली/रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा-संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत देश में वामपंथ उग्रवाद की मौजूदा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावति 13 जिलों सहित 9 राज्यों के कुल 38 जिलों को 'विरासत एवं प्रबल' ('लीगेसी एंड थ्रस्ट') श्रेणी में रखा गया है। यानी नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी इन जिलों में सुरक्षा उपायों के साथ विकास पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। वामपंथ उग्रवाद को दोबारा पनपने से रोकने के लिए और मौजूदा स्थिति को ज्यादा मजबूत बनाने के मकसद से 'विरासत एवं प्रबल' श्रेणी वाले जिलों में कुछ समय तक सुरक्षा संबंधी उपाय जारी रहेंगे।

वामपंथी उग्रवाद की समस्या का पूर्ण समाधान, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा उपायों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से

प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर गौर करना था। स्थानीय लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया गया। उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस पर भी गृह मंत्रालय का खास फोकस रहा। गृह मंत्रालय की ताजा समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के परिणामस्वरूप, देश वामपंथ उग्रवाद की समस्या से मुक्त हो चुका है।

मार्च व अप्रैल में हुई समीक्षा रिपोर्ट का नतीजा

गृह मंत्रालय ने मार्च व अप्रैल में एलडब्लूई से प्रभावित रहे जिलों की व्यापक समीक्षा की थी। इसमें वामपंथी हिंसा की तीव्रता, सशस्त्र काडरों की उपस्थिति और उनकी हिंसात्मक क्षमता, नक्सलवाद से जुड़े संगठनों की वर्तमान स्थिति तथा 'मुक्त क्षेत्रों' की उपस्थिति जैसे प्रमुख मानकों का समग्र मूल्यांकन किया गया। समीक्षा के बाद सामने आया कि अब कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित नहीं है। अपेक्षित विकास से वंचित कुछ जिलों में सुरक्षा एवं विकासात्मक उपायों को बनाए रखना आवश्यक है। एसआरई योजना के तहत 38 वामपंथ उग्रवाद से मुक्त जिलों को दो श्रेणियों में बांटा गया। 'विरासत एवं प्रबल' श्रेणी में 37 जिले और 'चिंताजनक जिला', इस श्रेणी में झारखंड के सिंहभूम जिले को शामिल किया गया।

छत्तीसगढ़ के इन जिलों को किया गया शामिल

'विरासत एवं प्रबल' श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, धमतरी, कबीरधाम, कोंडागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजानंदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, गरियाबंद, सुकमा व दांतेवाड़ा को शामिल किया गया है। इन जिलों में पूर्व की भांति सुरक्षा उपायों में कमी नहीं की जाएगी।

इन 8 राज्यों केविरासत एवं प्रबल' जिलों की सूची

ओडिशा : बौध, सुन्दरगढ़ (राऊरकेला पुलिस जिला), कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगड़ा, कंधमाल
झारखंड : पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, छतरा, लातेहार
बिहार : औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय
तेलंगाना : भद्रादी-कोठागुडेम, मुलुगु
महाराष्ट्र : गढ़चिरोली, गोंदिया
मध्य प्रदेश : बालाघाट, मंडला
आंध्र प्रदेश : अल्लूरी सीतारामराजू
पश्चिम बंगाल : झारग्राम

गृहमंत्रालय ने अभी कुछ समय तक सुरक्षा उपाय व सुरक्षाबलों की तैनाती तथा क्षेत्र के विकास को फोकस नियम बनाया है।

वन्यजीव तस्करों पर कड़ी कार्रवाई, सांभर शिकार मामले में 3 गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन मंत्री श्री केदार कश्यप के सख्त निर्देशों के बाद वन विभाग ने वन्यजीव तस्करों और शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में मोहला वनमंडल के दक्षिण मानपुर क्षेत्र में सांभर का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

वनमण्डलाधिकारी दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि विगत 6 अगस्त की शाम को वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत बागडोगरी के रेंगाटोला

गांव में कुछ लोग सांभर का मांस पका रहे हैं। सूचना मिलते ही दक्षिण मानपुर के परिक्षेत्र अधिकारी और मानपुर के उपवनमंडलाधिकारी ने सर्च वारंट लेकर तुरंत मौके पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पका हुआ मांस बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि खेत में फंसे सांभर के बच्चे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई थी। वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों काजूराम (पिता मसरूराम), रघुराम (पिता मनीराम) और राहुल (पिता सुकलु) को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबागढ़ चौकी में पेश किया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राजनांदगांव जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है। इस संदर्भ में वन मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों के संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकारियों के खिलाफ ऐसे ही कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे।

डोप टेस्ट में पॉजिटिव मिला एक पायलट फ्लाइट टर्बुलेंस में कई यात्री हुए थे जख्मी

नईदिल्ली ए.। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान एआई 2379 में गंभीर टर्बुलेंस की घटना के बाद जांच में नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, विमान के कमांड में रहे पायलट के दिल्ली पहुंचने के बाद कराए गए अनिवार्य डोप टेस्ट में साइको एक्टिव पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक एअर इंडिया की तरफ से इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं आयी है। जबकि, जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को फिलहाल उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है।

एआई 2379 एयरबस ،320 विमान है, जो फुकेट से दिल्ली आ रहा था। उड़ान के दौरान विमान को अचानक गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए इसकी ऊंचाई करीब 300 फीट तक कम हो गई। इस दौरान यात्री और चालक दल के सदस्य अपनी सीटों से उछल गए। घटना में कई यात्रियों और क्रू सदस्यों को चोटें आईं। इस घटना की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) कर रहा है।

पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता की पहल : रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तीन 'अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम' का शुभारंभ

■ कतार से मुक्ति,बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए 24 घंटे मिलेगा खाद्यान्न- मंत्री बघेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडएस) को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने शनिवार को प्रदेश के पहले तीन 'अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम' का रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन शुभारंभ किया।

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के माध्यम से राशनकार्डधारी हितग्राही अब अपनी सुविधा के अनुसार 24म7 घंटे चावल प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मशीन की स्क्रीन पर राशनकार्डधारी को अपना आधार नंबर अथवा राशनकार्ड नंबर दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा।

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की खासियत यह है कि छत्तीसगढ़ के राशनकार्डधारियों के साथ.साथ अन्य राज्यों के राशनकार्डधारी भी 'वन नेशन, वन राशनकार्ड' योजना के तहत बायोमेट्रिक

प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रवासी श्रमिकों और अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले हितग्राहियों के लिए भी राशन प्राप्त करना आसान होगा।

छत्तीसगढ़ ग्रेन एटीएम संचालित करने वाला देश का पांचवां राज्य

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम वर्तमान में उत्तराखंड, मेघालय, गुजरात और ओडिशा में संचालित हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ भी ग्रेन एटीएम संचालित करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। प्रदेश में तीन ग्रेन एटीएम की शुरुआत पीडीएस व्यवस्था में तकनीक के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पारदर्शी पीडीएस की दिशा में भी यह प्रभावी कदम है।

भारतीय कानून मानने ही होंगे, मेटा को सरकार का साफ संदेश, डीपफेक पर सख्ती की तैयारी

नईदिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में मेटा के प्लेटफ़ॉर्म को भारतीय कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप काम करना होगा। बातचीत का केंद्र कंपनी के पूरे एल्गोरिदम को बदलना नहीं, बल्कि कंटेंट मॉडरेशन, छ्स्रू डीपफेक और सिंथेटिक कंटेंट से जुड़े मौजूदा सिस्टम को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। सरकार खास तौर पर स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों की बेहतर समझ, संवेदनशील मामलों में मानव समीक्षा तथा हटाए गए हानिकारक कंटेंट को दोबारा रिकमेंड होने से रोकने पर जोर दे रही है। मेटा और स्द्भद्धह्लड्ड के बीच तकनीकी बातचीत जारी रहेगी और अगले सप्ताह फिर बैठक होने की संभावना है। हालांकि कुछ चिंताएं अब भी बनी हुई हैं, अधिकारियों ने कहा कि मेटा के साथ हालिया बातचीत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस और कंटेंट पॉलिसी पूरी तरह भारतीय कानूनों के अनुरूप हों।

सूत्रों ने बताया कि देश के बाहर काम करने वाली मेटा की टीमें कई बार भारत के सांस्कृतिक संदर्भ और स्थानीय संवेदनशीलताओं को पूरी तरह नहीं समझ पाती हैं। ऐसे में कंटेंट को सही तरीके से मॉडरेट करने के लिए मेटा को स्थानीय स्तर पर अधिक इनपुट की जरूरत है। इसमें भारतीय भाषाओं के साथ-साथ देश की अलग-अलग सांस्कृतिक बारीकियों और सामाजिक संदर्भों की बेहतर समझ भी शामिल है।

बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (छ्स्रू) के मुद्दे पर सरकारी सूत्रों का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि ऐसे कंटेंट के मामले में जीरो टॉलरेंस और किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अधिकारियों के मुताबिक, किसी प्लेटफ़ॉर्म पर इस तरह का कंटेंट मौजूद रहना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही, उन्होंने कहा कि मेटा को ऐसे मामलों से निपटने के लिए अधिक मजबूत और सक्रिय कदम उठाने होंगे। केवल भरोसा दिलाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कंपनी को अपनी कार्रवाई के जरिए यह साबित करना होगा कि वह ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

अलग कंटेंट क्यों दिखा रहा है मेटा का रिकमेंडेशन सिस्टम?

सरकार ने मेटा के रिकमेंडेशन और वायरल होने वाले एल्गोरिदम को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों ने सवाल किया कि यूजर्स को अक्सर उनकी बताई गई पसंद से अलग कंटेंट क्यों दिखाई देता है। सूत्रों के मुताबिक, यह स्थिति रिकमेंडेशन सिस्टम में मौजूद संभावित कमियों की ओर इशारा करती है। इन कमियों को समझने और उन्हें दूर करने की जरूरत है, ताकि यूजर्स तक पहुंचने वाले कंटेंट को लेकर सिस्टम अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सके।

संपादकीय

भुगतान पर अड़ंगा

यूपीआई लेन-देन पर सेवा शुल्क

यूपीआई लेन-देन पर बैंकों और भुगतान प्रोसेस करनेवालों को शुल्क लगाने की इजाजत देने का सरकार का फैसला हालांकि अभी लंबित है, लेकिन इसने कई नीतिगत सवाल खड़े कर दिये हैं। किसी आधिकारिक निर्णय की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारियां नजर आ रही हैं। जो इकलौता आधिकारिक बदलाव किया गया है वह है 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट' में संशोधन, जिससे अब सरकार को यह अधिसूचित करने की इजाजत मिलेगी कि किस-किस तरह के लेन-देन पर शुल्क लग सकता है। यह 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' के जरिए किया गया, जिसे हाल ही में लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित किया गया। इस कानून से पहले, यूपीआई और 'रूपे' डेबिट कार्ड लेन-देन साफ तौर पर किसी भी तरह के शुल्क से मुक्त थे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस शुल्क की इजाजत एक-डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों द्वारा हुए लेन-देन और 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन के लिए ही दी जा सकती है। इससे सभी यूपीआई लेन-देनों में से लगभग 5 फीसदी पर ही शुल्क लगेगा। हालांकि, संशोधित कानून सरकार को यह गुंजाइश बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। यह भी डर है कि व्यापारी इस लागत का बोझ डालेंगे उपभोक्ताओं पर, जो नकदी की ओर लौटना पसंद करेंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल नि:शुल्क है। खैर, इस मुद्दे को भुगतान इकोसिस्टम के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। यूपीआई को साल 2020 में नि:शुल्क किया गया। भुगतान कंपनियों का कहना है कि वे तब से यूपीआई को बनाये रखने और चलाने का खर्च उठा रही हैं। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल में कहा, यूपीआई के लिए किसी व्यक्ति को तो भुगतान करना पड़ेगा। शायद उनका मतलब था कि अब वह किसी व्यक्ति भुगतान प्रोसेस करनेवाले या बैंक नहीं होने चाहिए।

> "यह 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' के जरिए किया गया, जिसे हाल ही में लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित किया गया। इस कानून से पहले, यूपीआई और 'रूपे' डेबिट कार्ड लेन-देन साफ तौर पर किसी भी तरह के शुल्क से मुक्त थे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस शुल्क की इजाजत एक-डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों द्वारा हुए लेन-देन और 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन के लिए ही दी जा सकती है। इससे सभी यूपीआई लेन-देनों में से लगभग 5 फीसदी पर ही शुल्क लगेगा। हालांकि, संशोधित कानून सरकार को यह गुंजाइश बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है।

हालांकि, लागत का बोझ अकेले इन भुगतान कंपनियों ने नहीं उठाया है। करदाता पहले ही इसका कुछ हिस्सा वहन कर रहे हैं। साल 2021 में, सरकार एक योजना लेकर आयी जिसके तहत उसने छोटे व्यापारियों द्वारा 2,000 रुपये तक के लेन-देनों की प्रोसेसिंग लागत की आंशिक भरपाई के लिए, भुगतान प्रोसेस करनेवालों और बैंकों को सब्सिडी का भुगतान किया। सरकार इसके लिए पहले ही 11,349 करोड़ रुपये भुगतान कर चुकी है, तथा साल 2026-27 के लिए और 2,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। सवाल है कि क्या ग्राहकों और व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि उनके करों में से कुछ का इस्तेमाल पहले ही इस काम के लिए किया जा रहा है। इस धारणा को लेकर भी कुछ गुस्सा है कि सरकार ने नोटबंदी के जरिए लोगों को यूपीआई इस्तेमाल करने की ओर इसीलिए धकेला ताकि अब उस पर शुल्क वसूलने की इजाजत दे सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ऐसे शुल्क से भुगतान कंपनियों को बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में ज्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी। यूपीआई के विकास के लिए भुगतान की खातिर आरबीआई के पास संसाधन हैं। इसका इस्तेमाल करने से उस भारी अधिशेष में बस थोड़ी-सी कमी आयेगी जो वह हर साल केंद्र को हस्तांतरित करता है, लेकिन इससे सरकार एक ऐसे निर्णय से बच जायेगी जिसकी अलोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक : सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और विकसित भारत की मजबूत नींव

जगत प्रकाश नड्डा

भारत ने पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया है। सरकारी और निजी क्षेत्र में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जांच केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह सरकार की ऐसी नीतियों को दर्शाता है, जिनका केंद्र आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए काम किया है। इन लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है कि देश में लोगों द्वारा अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कमी आई है। यह खर्च पहले 65 प्रतिशत तक था, जो अब घटकर 43 प्रतिशत रह गया है।

जिला अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशु से लेकर बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर मरीज तक, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसेमंद, अच्छी गुणवत्ता वाले और किफायती चिकित्सा उपकरण बेहद जरूरी हो गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने, गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने, बीमारियों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर निवेश किया जा रहा है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब जोर एक आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने पर है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और सस्ता, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय मजबूत बनाना है।

पहले ,भारत कई आधुनिक और जटिल चिकित्सा उपकरणों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर था। इन तकनीकों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो हुआ, लेकिन इससे इलाज की लागत बढ़ी, आपूर्ति व्यवस्था पर बाहरी निर्भरता बनी रही और इन उपकरणों की पहुंच सीमित रही। इसी जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 में देश के भीतर आधुनिक चिकित्सा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाना और जांच की लागत कम करना है। सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के पूरे क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा उपकरण पार्क और दवा एवं चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना शामिल हैं।

इन पहलों से देश में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, नए शोध, निवेश और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है। नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 50 से अधिक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का देश में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है, जो वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि भारत धीरे-धीरे दुनिया के चिकित्सा तकनीक क्षेत्र में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभर रहा है।

सिर्फचिकित्सा उपकरणों का निर्माण केंद्र बनने के अलावा, भारत तेजी से आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपना भी रहा है, ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आधुनिक जांच सुविधाओं, शरीर की अंदरूनी तस्वीर लेने वाली मशीनों, शरीर में लगाए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों, गहन चिकित्सा की मशीनों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराने से मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होता है। साथ ही इलाज की गुणवत्ता और समय पर इलाज मिलने में भी सुधार होता है। देश में ही चिकित्सा उपकरण बनने से विदेशों से आयात पर निर्भरता घटती है, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होती है और लागत कम करने के अवसर बढ़ते हैं।

भारत का विश्व स्तर पर पहचान बना चुका दवा उद्योग, मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता, तेजी से फैलता डिजिटल ढांचा, तेजी से बढ़ता नए उद्यमों का क्षेत्र और कुशल मानव संसाधन अगली पीढ़ी की चिकित्सा तकनीक विकसित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर (एसएमडी) , इंटरनेट से जुड़े चिकित्सा उपकरण, रोबोट आधारित तकनीक और दूर से जांच जैसी नई तकनीकों में भारत के पास देश और दुनिया की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए नए समाधान विकसित करने के बड़े अवसर हैं।

जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां दुनिया के बाजार में विस्तार कर रही हैं, गुणवत्ता भी भारत में बने चिकित्सा उपकरणों की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। सरकार नियामक व्यवस्था को मजबूत करने, मान्यता प्राप्त जांच सुविधाओं का विस्तार करने, चिकित्सा उपकरणों की प्रभावशीलता से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रही है। इससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी मजबूत होगी।

दुनिया के स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा देने वालों, नए उद्यमों और निवेशकों के बीच करीबी सहयोग जरूरी है। जब प्रयोगशालाओं में तैयार विचार आसानी से कारखानों तक और वहां से मरीजों तक पहुंचते हैं, तभी नए आविष्कारों को वास्तविक लाभ में बदला जा सकता है। सरकार ऐसी स्थिर और पारदर्शी नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनसे शोध, निवेश, तकनीकी साझेदारी और कारोबार करना आसान हो।

भारत जैसे-जैसे विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास एक-दूसरे को और मजबूत करेंगे। एक मजबूत चिकित्सा उपकरण उद्योग उच्च मूल्य वाले उत्पादन, कुशल रोजगार, निर्यात और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सस्ती, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय अधिक मजबूत बनेंगी।

भारत का चिकित्सा तकनीक क्षेत्र एशिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है। फिलहाल इसका आकार 15 से 16 अरब डॉलर है और यह करीब 12 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस वजह से यह देश के सबसे तेजी से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्रों में से एक बन गया है।

विकसित भारत का लक्ष्य गुणवत्ता, नए आविष्कार और सभी को साथ लेकर चलने के आधार पर दुनिया में नेतृत्व करने पर जोर देता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि नई चिकित्सा तकनीकें भारत की प्रमुख स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करें। इनमें माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, आपातकालीन चिकित्सा, कैंसर, हृदय रोग और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत लगातार एक आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक व्यवस्था तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल भारत में चिकित्सा उपकरण बनाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को समय पर अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत को दुनिया के एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करना है।

(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं।)

क्यूआर कोड महज जानकारी का जरिया है, हाइजीन का सबूत नहीं

एन. रघुरामन

स्ट्रीट फूड सिर्फ लखनऊ ही नहीं, इंदौर जैसे शहरों की भी शान है। या फिर कहें कि हर शहर के कुछ खास हिस्से उसकी शान होते हैं, जैसे मुम्बई में घाटकोपर की 'खाऊ गली', बांद्रा का एल्को मार्केट, दिल्ली में चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और करोल बाग, जयपुर में चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार और एमआई रोड। गुजरात के कई शहरों को तो भूलना ही नहीं चाहिए।

हाल ही में मुझे पता चला कि अहमदाबाद की क्यूआर कोड आधारित फूड सेफ्टी और फीडबैक व्यवस्था से प्रेरित होकर लखनऊ के लोगों ने भी अपने नगर निगम और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से शहर के फूड हब्स में हाइजीन और पारदर्शिता बेहतर करने के लिए ऐसी ही व्यवस्था अपनाने की मांग की है।

इससे ग्राहक दुकानों पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करके विक्रेता का रजिस्ट्रेशन देख सकेंगे, हाइजीन नियमों का पालन जांच सकेंगे और शिकायत या फीडबैक दे सकेंगे। शुरुआत में हजरतगंज, अमीनाबाद, चौक और गोमती नगर इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार है।

यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब समय-समय पर निरीक्षण होते हैं तो यह क्यूआर-लिंक्ड ग्रिवेंस प्लेटफॉर्म जवाबदेही बढ़ा सकता है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई में अधिकारियों की मदद भी कर सकता है, लेकिन हाइजीन जैसी रोजमर्रा की समस्या में यह कैसे कारगर होगा?

चूंकि स्ट्रीट वेंडर्स ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते तो सिर्फ एक क्यूआर कोड हाइजीन की गारंटी नहीं देता। यह इतनी-सी गारंटी देता है कि कोई व्यक्ति जानकारी ले सकता है। यह विश्वसनीयता भी इस बात पर निर्भर करती है कि जानकारी कौन कलेक्ट करता है, उसे सत्यापित करता है और यह कितनी बार अपडेट की जाती है।

जब करोड़ों भारतीय हर हफ्ते स्ट्रीट फूड खाते हैं तो क्या हर आउटलेट पर क्यूआर कोड लगाना हाइजीन सुधारने के लिए पर्याप्त है? हो भी सकता है और नहीं भी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे किसी भी बड़े शहर में देखिए, स्ट्रीट फूड ऑफिस-वर्कर्स, स्टूडेंट्स, पर्यटकों और प्रवासी कामगारों के लिए रोज का भोजन है।

चूंकि यह असंगठित बाजार है तो अनुमानत: इसका टर्नओवर कुछ लाख करोड़ रुपए का है। यह सब्जी, मसाले, डेयरी, मीट, ईंधन, बर्तन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने वाले ऐसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार देता है, जो हाइजीन को लेकर बहुत कम शिक्षित होते हैं।

फिर सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे वेंडर्स की रेटिंग किसे करनी चाहिए? हम सभी सोचते हैं कि हमारे ग्राहक सबसे बेहतर रेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हममें से अधिकतर यह आकलन नहीं कर सकते कि क्या कुकिंग ऑइल बार-बार इस्तेमाल किया गया है, क्या पानी पीने योग्य है या सामग्री दूषित तो नहीं। लेकिन एक और समस्या भी है।

हममें से जो लोग मूल्यांकन में बेहतर थे, अचानक इंफ्लुएंसर्स की तरह व्यवहार करने लगते हैं और पक्षपाती हो जाते हैं। इधर, हाइजीन और नियमों के पालन को परखने के लिए प्रशिक्षित फूड सेफ्टी इंस्पेक्टरों की संख्या हमेशा कम होती है।

अनियमित निरीक्षण और इंस्पेक्टरों के विवेकाधिकार के चलते घूसखोरी की गुंजाइश भी बन सकती है। थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट करने वाले स्वतंत्र ऑडिटर या मान्यता प्राप्त एजेंसियां महंगी होती हैं और इन्हें हजारों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू कर पाना भी कठिन है।

असल मुद्दा यह गलतफहमी है कि टेक्नोलॉजी गवर्नेंस की जगह ले सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यूआर कोड बता सकता है कि विक्रेता कौन है। लेकिन यह नहीं बता सकता कि तेल दस बार तो इस्तेमाल नहीं हो चुका, पानी दूषित तो नहीं या कच्चा मीट सुरक्षित तरीके से रखा गया था या नहीं।

इसके लिए प्रशिक्षित इंस्पेक्टर, समय-समय पर लैब टेस्ट और ऐसे विक्रेता चाहिए, जो हाइजीन का महत्व समझते हों। अधिकतर स्ट्रीट वेंडर्स जानबूझकर अन-हाइजीनिक नहीं होते। उनमें से बहुत-से अप्रशिक्षित होते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम उन्हें ट्रेनिंग दें, न कि सिर्फ नियमों में बांधें।

फंडा यह है कि कि सबसे मजबूत समाधान किसी एक मैकेनिज्म पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि ऐसा लेयर्ड सिस्टम तैयार करना है, जिसमें तकनीकी, निरीक्षण, विक्रेता और ग्राहक- सभी की अपनी अलग भूमिका हो।

शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाना बहुत बड़ी चुनौती!

दीपक कुमार त्यागी

देवाधिदेव भगवान महादेव के प्रिय श्रावण मास में मां गंगा के जल से अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए दिल्ली और आसपास स्थित विभिन्न राज्यों के शिवभक्तों का उत्तराखंड से कांवड़ लाने के लिए अब तांता लगना शुरू हो गया है। इस बार तो कांवड़ यात्रा के शुरुआती दिनों में ही शिवभक्तों की भारी भीड़ सड़कों पर नज़र आने लगी है। कांवड यात्रा के मद्देनजर ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान आदि में शिवभक्तों की सुरक्षा के सिस्टम ने बेहद ही चाक-चौबंद व्यवस्था की है। शिवभक्तों के लिए रेलवे, परिवहन, विधुत विभाग आदि ने भी विशेष तैयारियां की हैं। सिस्टम ने पवित्र श्रावण मास में देवाधिदेव भगवान महादेव के करोड़ों शिवभक्तों को शांतिपूर्ण व भक्तिमय वातावरण में सकुशल कांवड़ यात्रा करवाने के लिए सुरक्षा, भोजन, पेयजल, चिकित्सा आदि व्यवस्था की बड़े पैमाने पर तैयारियां की है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान आदि का पुलिस-प्रशासन दिन-रात एक करके अपने पूरे दल-बल के साथ सड़कों पर उतरकर के धरातल पर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है।

हालांकि पुलिस-प्रशासन को इस वर्ष कांवड़ियों की संख्या में भारी इज़ाफा होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में विशेषकर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के पुलिस-प्रशासन के ऊपर पर एक तरफ तो कांवड़ियों के लिए विभिन्न आवश्यक व्यवस्था बनाने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ़ चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने कि अहम जिम्मेदारी है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का वर्ष होने के चलते वहां के सिस्टम के सामने भगवान शिव की भक्ति के वातावरण को बनाएं रखने की बड़ी चुनौती खड़ी है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सिस्टम के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिवभक्त कांवड़ियों का सेवाभाव के साथ पलक-पांवड़े बिछाकर के स्वागत किया जाता है और कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, इस स्थिति ने पिछले कई सालों से शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या में भारी इज़ाफ़ा करने का कार्य कर दिया है। जिसके चलते कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए धरातल पर एक बेहद फुलप्रुफ व्यवस्था बनाते हुए चाक-चौबंद व्यवस्था करना चुनौती पूर्ण कार्य बन गया है।

हर वर्ष की तरह ही कांवड़ यात्रा में पुलिस-प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह लाखों शिवभक्तों के बीच छिपे हुए चंद अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों व नशेड़ियों की कैसे पहचान करें। हालांकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पुलिस-प्रशासन के पास भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रण करने व उनके लिए समुचित व्यवस्था करने का दशकों पुराना लंबा अनुभव है, जिस अनुभव के ही बलबूते पर ही इन राज्यों का सरकारी अमला हर वर्ष ऐसे मेलों में उत्पन्न विकट से भी विकट परिस्थितियों से भी आसानी से निपट लेता है। लेकिन इस बार तो शुरूआती दिनों से ही शिवभक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ती नज़र आ रही है, बड़ी संख्या में ही कांवड़िए मां गंगा का दिव्य जल लेकर के अपने गंतव्य स्थल की तरफ़ वापस चल दिए और एक-एक दिन के साथ ही शिवभक्त कांवड़ियों की यह संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ हुड़दंगियों के द्वारा बवाल किये जाने की भी घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। जिसके चलते ही उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में शुरूआती दौर के दिनों में ही कांवड़ यात्रा मार्ग के अधिकांश रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट करते हुए बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक को वन-वे तक भी करना पड़ गया है, हालांकि ऐसा करने से लोगों को काफी असुविधा भी हो रही है, लेकिन पुलिस-प्रशासन के पास इसके अलावा कोई विकल्प अभी तो मौजूद नहीं है।

वैसे भी हमारे प्यारे देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस स्थिति में शिवभक्त कांवड़ियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए ट्रैफिक डायवर्ट व वन-वे करने की यह व्यवस्था सिस्टम का बेहद जरूरी कदम है। इसलिए ही उत्तराखंड से लेकर के कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर अब चप्पे-चप्पे पर होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, पीएसी, आरएएफ, एटीएस आदि तक का बेहद ही सख्त पहरा नज़र आने लग गया है। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम दल-बल के साथ तैनात हैं, कांवड़ यात्रा मार्ग पर जगह-जगह अग्निशमन विभाग के जांबाजों, जिला प्रशासन की टीम, चिकित्सा विभाग की टीम, नगर निगम, नगर पालिका परिषद जिला पंचायत व ग्राम पंचायत आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों ने चौबीस घंटे मोर्चा संभाल रखा है। वहीं पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी स्वयं पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं और हर व्यवस्था को स्वयं परखने का कार्य कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह का कोई भी विवाद खड़ा होने पर पुलिस-प्रशासन तुरंत सूझबूझ से मामले को शांत कराते हुए, दोषियों के ख़िलाफ सख़्त कार्यवाही करते हुए माहौल को सामान्य करने का कार्य बखूबी कर रहा है। सरकार व सिस्टम कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई लापरवाही व कोई भी चूक बिल्कुल भी नहीं चाहता है।

बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सख्ती का आलम यह हो गया है कि गाजियाबाद तक में भी 29 जुलाई से ही भारी वाहनों के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग को बंद करते हुए रास्ते के बहुत सारे कट बंद कर दिए है और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रास्ते वन-वे करने की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वैसे कांवड़ यात्रा के दौरान हर वर्ष ही क्षेत्रवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अलग कांवड़ यात्रा मार्ग ना होने से पुलिस-प्रशासन के पास कम से कम फिलहाल तो अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था का आलम देखें तो गाजियाबाद जनपद में ही, पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड, नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल व अन्य सभी आवश्यक विभागों के मुखिया अपनी पूरी टीम के साथ चौबीसों घंटे मुस्तैद खड़े हुए नज़र आते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने जनपद में पड़ने वाले करीब 80 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग को बीटों में विभाजित करके अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी दी हैं। उन्होंने स्थाई कंट्रोल रूम, मुख्य कंट्रोल रूम, सब कंट्रोल रूम और अस्थाई कंट्रोल रूम बनाए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग को लाइट व सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह-जगह पुलिस ने बैरियर लगाए गए हैं। सार्वजनिक घोषणा प्रणाली बनाई गई है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के अनुसार व्यवस्था बनाने की तैयारी। सुरक्षा के मद्देनजर नियमित रूप से डॉग स्कवायड, बम निरोधक दस्ता और लोकल इंटेलीजेंस की टीम के साथ पुलिस चेकिंग अभियान चलाते हुए, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने में दिन-रात व्यस्त है। पीआरवी एवं चीता मोबाइलों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगाया गया है। घाटों पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम तैनात की गयी हैं। दमकल की गाड़ियां विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की टीम तैनात हैं, एंबुलेंस तैनात हैं, पथ-प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है, पेयजल की व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 6 कंट्रोल रूम और 2 विशेष हेल्पलाइन शुरू की हैं। 11 जोनल, 24 सेक्टर और 108 सब मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हालांकि पुलिस-प्रशासन के द्वारा की गयी बेहद चाक-चौबंद व्यवस्था के बाद भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाले दिनों किसी भी तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों से निपटने की एक बड़ी चुनौती खड़ी है। क्योंकि यात्रा के दौरान कांवड़ छूने, कांवड़ के वाहनों से टकराने आदि छुटपुट बातों का बतंगड़ ना बने उससे निपटना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से देश में जिस तेज़ी से धैर्य व छोटे-बड़े की शर्म, आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता, आपसी सहयोग का भाव दिन-प्रतिदिन बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है, कांवड़ यात्रा मार्ग में इसका प्रभाव अब वर्ष दर वर्ष स्पष्ट रूप से नज़र आने लगा है। जिसके चलते ही अब तो बिना सिर-पैर के विवाद भी कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी चुनौती पैदा करने लग गए हैं। भगवान महादेव की कृपा से इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा दिव्य, अलौकिक, यादगार बन कर के सकुशल संपन्न होगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

सर्वधर्म सेवा संस्था ने रेलवे स्टेशन को भेंट की व्हीलचेयर

भिलाई। सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा अपनी निरंतर जनसेवा गतिविधियों के अंतर्गत आज पावर हाउस रेलवे स्टेशन, भिलाई में एक जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता हेतु व्हीलचेयर प्रदान की गई। संस्था के सदस्यों ने व्हीलचेयर स्टेशन मास्टर तनवीर इमामं को सौंपते हुए अनुरोध किया कि इसे ऐसे दिव्यांग, वृद्ध अथवा असहाय यात्रियों की सुविधा के लिए उपयोग में लाया जाए, जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। संस्था का उद्देश्य है कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले जरूरतमंद यात्रियों को समय पर सहायता मिल सके और उनकी यात्रा अधिक सुगम एवं सम्मानजनक बन सके।

रिटेंशन स्कीम में बदलाव के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

भिलाई। टाउनशिप में सेल प्रबंधन की आवास नीति में संभावित बदलाव और रिटेंशन प्रावधान खत्म होने की जानकारी सामने आने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। इस्पात मंत्रालय को भेजे गए डीपीआर में रिटेंशन का प्रावधान नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। 'भिलाई को बचाना है' मुहिम के तहत 500 से अधिक लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान भिलाई के मेन गेट पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। टाउनशिप में लाइसेंस आवास, लीज रजिस्ट्रेशन और रेंट रिटेंशन स्कीम से जुड़े मामलों को लेकर पहले से ही असमंजस की स्थिति है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि सालों तक भिलाई स्टील प्लांट में सेवा देने के बाद टाउनशिप में रहने वाले परिवारों के आवास का भविष्य अनिश्चित हो गया है।

भिलाई में दो दिवसीय अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन 19 से, देशभर से श्रोता और उद्घोषक आएंगे

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। इस्पात नगरी भिलाई में अखिल भारतीय रेडियो-श्रोता सम्मेलन का आयोजन 19 और 20 अगस्त को होने जा रहा है। जिसमें देश भर से 500 से ज्यादा रेडियो श्रोता शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरणा -सदन, सेक्टर- 6 में कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक रखी गई।

इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक परसराम साहू 'गुरुजी' ने बताया कि आयोजन में पूरे भारत के लगभग 18 राज्यों से 500 रेडियो श्रोता एवं विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों तथा कम्युनिटी रेडियो के उदघोषकों की उपस्थिति रहेगी। आयोजन में दोनों दिन रेडियो सेट, छत्तीसगढ़ी गहने, कलेवा, सिनेमा, साहित्य, पेंटिंग और बस्तर आर्ट की

प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होगी।

दो दिवसीय सम्मेलन में बुधवार 19 अगस्त को मुख्य अतिथि देवेन्द्र यादव विधायक भिलाई नगर होंगे। अध्यक्षता अशोक बजाज, संयोजक छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ रायपुर करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉ. उदय कुमार धाबर्डे मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा प्रमुख बीएसपी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग होंगे।

20 अगस्त को महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल होंगे। अध्यक्षता अशोक बजाज भाजपा प्रदेश प्रभारी मंत्री, रायपुर करेंगे। विशिष्ट अतिथि- तरुणा साहू (पंडवानी लोक गायिका) राजनांदगांव और डॉ. संतोष जाधव (सहायक कार्यक्रम निदेशक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई होंगे।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय

बीएसपी में 'इको केयर एवं आपदा प्रबंधन': मानसिक एवं भावनात्मक सुदृढ़ता पर विशेष सत्र

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। बीएसपी के विभिन्न विभागों में राष्ट्रव्यापी 'इको केयर एवं आपदा प्रबंधन अभियान' के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से मानसिक एवं भावनात्मक सुदृढ़ता, सकारात्मक सोच तथा आपदा एवं संकट की परिस्थितियों में मानसिक तैयारी पर केंद्रित विशेष संवाद एवं प्रेरक सत्रों का आयोजन किया गया।

कोक ओवन विभाग में आयोजित विशेष संवाद सत्र में कार्यकारी मुख्य महाप्रबंधक (कोक ओवन) ओपी भट्ट तथा विशिष्ट अतिथि वक्ता ब्रह्मकुमार पीयूष, आंचलिक समन्वयक, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मकुमारी सुश्री मयंक जी उपस्थित रहीं।

सत्र को संबोधित करते हुए ब्रह्मकुमार पीयूष ने भावनात्मक सुदृढ़ता एवं संकट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्मिकों को स्वस्फूर्त, ऊर्जावान एवं प्रसन्नचित रहते हुए संयंत्र तथा सेल की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार रहना हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने की कुंजी है। उन्होंने सेल को 'महारत्न' से 'विश्व रत्न' की ओर ले जाने में प्रत्येक कार्मिक की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

वहीं, एम एंड यू कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सत्र में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (एम एंड यू) बीके बेहेरा, मुख्य महाप्रबंधक (उपयोगिताएं) जेपी सिंह सहित एम एंड यू जोन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। इसी क्रम में स्टील मेल्टिंग शॉप-2 में भी प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाप्रबंधक (एसएमएस-2) श्री कौशल कांत तिवारी, श्री एस देबसिकदर, श्री कमल अहमद शेख एवं श्री सोवन मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रमों में वक्ताओं ने मानसिक एवं भावनात्मक तैयारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संकट अथवा आपदा की स्थिति में केवल भौतिक संसाधन ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि शांत मन, सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन, आत्मबल और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक होती है। मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य, आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से कर सकता है।

सत्रों के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना प्रत्येक नागरिक एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी है। जल का विवेकपूर्ण उपयोग, विद्युत ऊर्जा की बचत, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, पर्यावरण संरक्षण तथा भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सभी का ध्यान आकृष्ट किया गया। इन संदेशों के माध्यम से वक्ताओं ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूक दृष्टिकोण अपनाते हुए जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया गया।

42 एमएलडी फिल्टर प्लांट आगजनी की होगी वैज्ञानिक जांच, ब्लीचिंग पर संदेह

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर में सुचारू पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने तथा रायपुर नाका स्थित 42 एमएलडी फिल्टर प्लांट में हुई आगजनी की घटना को लेकर महापौर अलका बाघमार ने अपने शासकीय आवास में जल विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक में जल कार्य प्रभारी लीना दिनेश देवांगन, लोक कर्म विभाग प्रभारी देवनारायण चंद्राकर, प्रभारी आयुक्त मानेंद्र साहू, जल विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रकाश थवानी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महापौर अलका बाघमार ने फिल्टर प्लांट में लगातार हुई आगजनी की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए घटना के कारणों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता में कमी अथवा विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महापौर ने आगजनी की घटना में जले ब्लीचिंग पावडर के सैंपल की गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लीचिंग पावडर की निष्पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए इसके नमूने बीआईटी दुर्ग एवं आईआईटी भिलाई की लैब में भेजे जाएं। साथ ही बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम दर पर उपलब्ध कराई गई ब्लीचिंग पावडर की गुणवत्ता की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। महापौर ने ब्लीचिंग पावडर, एलम सहित अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को फिल्टर प्लांट परिसर में एक साथ रखने के बजाय प्लांट से कुछ दूरी पर अलग-अलग सुरक्षित भंडारण केंद्र विकसित करने के निर्देश दिए।

बीएसपी जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र

'सेव अ लाइफ' अभियान के तहत सीपीसीआर कार्यशाला

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-बीएसपी के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग द्वारा विगत दिनों में 'सेव अ लाइफ' पहल के अंतर्गत मासिक 'हैंड्स-ओनली सीपीसीआर (कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन) प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन अस्पताल के ओपीडी कॉम्प्लेक्स में किया गया।

इस जन-जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय में आपातकालीन हृदयाघात की स्थिति में त्वरित जीवनरक्षक सहायता प्रदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक लोगों को सीपीसीआर तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है।

यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन डॉ. कुमुदनी, डॉ. अमित अग्रवाल एवं डॉ. प्रिया

पंकज ने एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के डीएनबी रेजिडेंट चिकित्सकों के सहयोग से किया।

कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा प्रशिक्षण मैनिकिन पर सीपीसीआर का अभ्यास किया। एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं डीएनबी रेजिडेंट्स ने प्रत्येक प्रतिभागी को सही तकनीक, शरीर की उचित स्थिति तथा प्रभावी चेस्ट कंप्रेशन की विधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। संवाद सत्र में आपातकालीन हृदय देखभाल एवं सीपीसीआर से संबंधित प्रतिभागियों के सभी प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का विशेषज्ञों द्वारा विस्तारपूर्वक समाधान किया गया।

जेएलएन अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की इस पहल का उद्देश्य अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ-साथ आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सहायता के लिए जागरूक और सक्षम बनाना है।

'आपात स्थिति में घबराएं नहीं, तुरंत सहायता करें' की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नियमित रूप से आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम समुदाय में जीवनरक्षक कौशल विकसित करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। कार्यक्रम में एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के चिकित्सकों, डीएनबी रेजिडेंट्स एवं अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

प्रथम के कार्यक्रम में महापौर अलका ने किया स्वच्छता किट का वितरण

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत महापौर अलका बाघमार अपने साथियों के साथ विवेकानंद सभागार पहुंचीं, जहां प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर स्वच्छता किट वितरण एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत खाद्य पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया।

प्रोग्राम कॉर्डिनेटर भोजराम साहू द्वारा जानकारी दिया गया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य देव नारायण चन्द्राकर, नीलेश अग्रवाल,शेखर चन्द्राकर,रंजीता पाटिल के अलावा क्लस्टर लीडर

पवन साहू ,रामेश्वरी साहू होमेंद्र देशमुख और कौशल्या साहू प्रथम सदस्य सहित आदि मौजूद रहें।

कार्यक्रम के दौरान महापौर ने हितग्राहियों को स्वच्छता किट वितरित की तथा स्ट्रीट फूड एवं छोटे व्यवसाय से जुड़े नागरिकों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली। शिविर के माध्यम से खाद्य व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों के पंजीयन एवं आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान लगभग 40 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता एवं हाइजीन से संबंधित किट प्रदान किए गए।

डीएवी स्पोर्ट्स मीट, एमएमपीएस जांता, बेमेतरा की टीम जीती

नंदिनी अहिवारा। डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल, नंदिनी माइंस में डीएवी स्पोर्ट्स मीट (क्लस्टर लेवल) 2026-27 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जोन के विभिन्न डीएवी विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि चिंताला श्रीकांत, जबकि विशिष्ट अतिथि ओमेन टेटे और एस. के. नायक रहे। स्कूल प्रभारी दिनेश कुमार जाधव ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रभावी माध्यम हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, योग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे और वुशू की स्पर्धाएं हुईं। कबड्डी अंडर-14 और अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्गों में डीएवी एमएमपीएस जांता, बेमेतरा की टीमों ने अपना वर्चस्व कायम करते हुए पहला स्थान हासिल किया।

सीएनसी सिमुलेशन द्वारा तकनीकी दक्षताओं का विकास

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-बीएसपी के मानव संसाधन-लर्निंग एवं डेवलपमेंट (एचआर-एलएंडडी) विभाग द्वारा तकनीकी दक्षताओं को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत संयंत्र के प्रचालन कार्यों में सलंग्न कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय 'इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सीएनसी सिमुलेशन' का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 कर्मचारियों ने भाग लिया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएसपी में प्रशिक्षण अधोसंरचना के उन्नयन तथा कर्मचारियों को आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं से संबंधित उद्योग-उपयोगी तकनीकी दक्षताओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएनसी की मूलभूत

अवधारणाओं, जी एवं एम कोड प्रोग्रामिंग, टर्निंग एवं मिलिंग सिमुलेशन, उन्नत प्रोग्रामिंग तकनीकों तथा सिमुलेशन आधारित व्यावहारिक मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया।

प्रशिक्षण सत्रों का संचालन श्री पंकज वर्मा एवं श्री आकाश कुमार उरकुड़े द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को उन्नत सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीएनसी प्रोग्रामिंग एवं मशीनिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सिमुलेशन आधारित इस प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित करने, प्रोग्रामिंग कौशल को मजबूत करने तथा सुरक्षित एवं नियंत्रित प्रशिक्षण वातावरण में सीएनसी प्रणालियों के संचालन एवं समस्या-निवारण की क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाया।

सीएनसी सिमुलेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एचआर-एलएंडडी सेंटर द्वारा सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी) के सहयोग से प्रशिक्षण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए संचालित की जा रही पहल का हिस्सा है। इस सहयोग के अंतर्गत एचआर-एलएंडडी सेंटर द्वारा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्क मैनेजमेंट तथा अब सीएनसी सिमुलेशन जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बीएसपी के उत्पादन विभागों की बदलती तकनीकी एवं दक्षता संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की क्षमताओं का निरंतर विकास करना है।

कार्यक्रम का सफल आयोजन महाप्रबंधक प्रभारी (एचआर-एलएंडडी) संजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में किया गया।

केपीएस में मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन

भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर में मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन हुआ। आयोजन सोरामी इवेंट्स ने किया। मुख्य अतिथि चेयरमैन, केईएस विजय कुमार गुप्ता ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रतिनिधियों से संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देने की अपील की। विद्यालय की प्राचार्य सबिता त्रिपाठी ने प्रतिनिधियों का स्वागत कर कूटनीति, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया। कैंपस कूटनीति, नेतृत्व और वैश्विक बातचीत के एक जीवंत मंच में बदल गया, क्योंकि औपचारिक पश्चिमी परिधान पहने युवा प्रतिनिधियों ने विश्व नेताओं की भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार दिखे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ने एजेंडा और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी दी।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
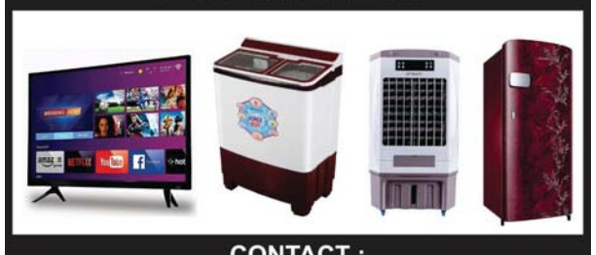
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

एग्रीस्टैक पंजीयन बना किसानों की डिजिटल सुरक्षा कवच

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को डिजिटल कृषि व्यवस्था से जोड़ने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह पंजीयन किसानों के लिए केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की कृषि सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। समय पर पंजीयन कराने वाले किसान अब इसे अपनी डिजिटल सुरक्षा कवच के रूप में देख रहे हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम भनौरा निवासी किसान नंदू राम सिंह ने समय रहते एग्रीस्टैक पंजीयन कराकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में उन्हें एग्रीस्टैक के महत्व की जानकारी नहीं थी, लेकिन राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा गांव में दी गई जानकारी के बाद उन्होंने तुरंत ग्राम पंचायत स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचकर अपना पंजीयन करा लिया। नंदू राम सिंह ने बताया कि पंजीयन की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम समय में पूरी हो गई। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बिना किसी परेशानी के उनका पंजीयन सफ्लतापूर्वक हो गया।

शिक्षा नीति में वैश्विक दृष्टिकोण और विलुप्त ज्ञान के पुनरुद्धार पर बल

रायपुर। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश छात्रों के सर्वांगीण विकास, नैतिक मूल्यों के उत्थान और मानसिक कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन वैज्ञानिक सोच, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, योग और दर्शन को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक व्यावहारिक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि के अवसर पर आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व विषय पर एक गरिमामय बौद्धिक विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय चेतना, चरित्र निर्माण और आधुनिक संदर्भों में प्राचीन ज्ञान के समावेश पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज दयाल ने कहा कि राष्ट्रगान जन-गण-मन केवल एक औपचारिक गीत नहीं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा, दर्शन और अध्यात्म का सार तत्व है।

महतारी वंदन से मिल रहा आर्थिक संबल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को लगातार मिल रहा है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने एक हजार रुपये की राशि सीधे अंतरित की जाती है। योजना की 30वीं किस्त भी महिलाओं के खातों में पहुंच चुकी है। नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि महिलाओं के लिए घर-परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक संबल बन रही है। कोंडागांव जिले के सरगीपाल पारा की महिलाओं के लिए भी महतारी वंदन योजना की राशि रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अलग-अलग महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर रही हैं। किसी के लिए यह राशि घर में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुओं की खरीद में काम आ रही है, तो कोई इससे रसोई गैस भरवा रही है।

जल सहेजकर गढ़बेंगाल ने गढ़ी नई राहः 3.91 करोड़ रुपए का स्टॉपडेम बना नारायणपुर में किसानों की समृद्धि का आधार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में गढ़बेंगाल में स्टॉपडेम का निर्माण जल संरक्षण और कृषि विकास के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे भूजल स्तर में सुधार होता है और किसानों को सालभर सिंचाई के लिए पानी मिलता है। नारायणपुर जिले के गढ़बेंगाल और कुम्हली गांव के खेतों में अब हर मौसम में हरियाली लहलहाएगी।

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में लगभग 3.91 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किए गए गढ़बेंगाल स्टॉपडेम ने क्षेत्र में जल संरक्षण और कृषि विकास की एक नई इबारत लिख दी है। वर्षा जल के संचयन और बेहतर प्रबंधन का यह प्रयास अब नारायणपुर के वनांचल में टिकाऊ खेती और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन चुका है।

105 हेक्टेयर कृषि भूमि को सीधी सिंचाई सुविधा मिलेगी: जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित बारिश के कारण उपजे जल संकट से निपटने के लिए निर्मित यह स्टॉपडेम अब क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके बनने से गढ़बेंगाल और कुम्हली गांव की लगभग 105 हेक्टेयर कृषि भूमि को सीधी सिंचाई सुविधा मिलने लगी है। सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था होने से किसान अब केवल खरीफ फसल के भरोसे रहने के बजाय रबी सीजन में भी गेहूं, तिलहन और सब्जियों का बेहतर उत्पादन लेने के लिए उत्साहित हैं। पानी की निरंतर उपलब्धता से प्रति एकड़ फसल उत्पादकता बढ़ने के साथ ही किसानों की आय और खेती के प्रति उनका विश्वास दोनों मजबूत हो रहे हैं।

वर्षा जल के रुकने से आसपास के क्षेत्र में भू-जल स्तर में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया: यह स्टॉपडेम न केवल खेतों को सींच रहा है, बल्कि क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन और दैनिक जीवन को भी संबल दे रहा है। बहते हुए वर्षा जल के रुकने से आसपास के क्षेत्र में रीचार्जिंग तेजी से बढ़ी है, जिससे भू-जल स्तर में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, तेज बारिश के दौरान पानी के अनियंत्रित बहाव को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोका जा सका है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। वहीं, ग्रामीणों और मवेशियों के लिए वर्षभर निस्तारी जल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होने से दैनिक जीवन की पानी संबंधी जरूरतें भी आसानी से पूरी हो रही हैं। गढ़बेंगाल स्टॉपडेम की सफ्लता के पीछे स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय जनभागीदारी और सजगता भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रही। निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों के सतत सहयोग से ही यह परियोजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हो सकी। जल संरक्षण के इस सामूहिक प्रयास ने स्थानीय लोगों में जल संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता का नया संचार किया है।

भू-जल स्तर और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक

गढ़बेंगाल स्टॉपडेम ने यह साबित कर दिया है कि यदि वर्षा जल का स्थानीय स्तर पर सही संचयन किया जाए, तो वह न केवल भू-जल स्तर और कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। जल संसाधन विभाग का यह प्रयास नारायणपुर जिले के सतत एवं समग्र विकास का एक उत्कृष्ट और प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है।

उद्योग मंत्री ने निगम के 04 वार्डो को दी 60 लाख रु. के विकास कार्यो की सौगात

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, सार्वजनिक उपक्रम व आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कोरबा जिले के पोड़ीबहार स्थित चन्द्रा समाज भवन में आयोजित भूमिपूजन लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान नगर पालिक निगम कोरबा के 04 वार्डो को 60 लाख रूपये के विकास कार्यो की सौगात दी। उन्होने वार्ड क्र. 32, 36, 37 व 24 में होने वाले व हुये विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण व भूमिपूजन किया, उन्होंने जिन विकास कार्यो का भूमिपूजन किया गया है, उसका शीघ्र कार्य प्रारंभ करने तथा पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन करते हुये समयसीमा में कार्यो को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड 32 अंतर्गत पोड़ीबहार में 25 लाख रूपये की लागत से चन्द्रा समाज के सामुदायिक भवन के पास सांस्कृतिक मंच, शेड व अन्य विस्तार कार्य किये गये हैं, जिसका लोकार्पण आज उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के हाथों किया गया। इसी प्रकार नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्र. 32 अंतर्गत पोड़ीबहार राठौर मोहल्ला में 05 लाख रूपये की लागत से मंच का निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 36 रिसदी बस्ती कन्हैया कंवर घर के पास 05 लाख रूपये की लागत से आर.सी.सी. छतदार सांस्कृतिक मंच का निर्माण, वार्ड क्र. 24 में शिव मंदिर के पास 05 लाख रूपये की लागत से एस.एस.रेलिंग, सौंदर्यीकरण एवं अन्य विस्तार कार्य, वार्ड क्र. 37 सिंचाई कालोनी रामपुर दुर्गा पण्डाल में 05 लाख रूपये की लागत से शेड निर्माण व अन्य विस्तार कार्य, वार्ड क्र. 36 डिंगापुर हनुमान मंदिर के पास यज्ञ शाला के समीप 07 लाख रूपये की लागत से सार्वजनिक मंच का निर्माण, वार्ड क्र. 36 डिंगापुर तालाब में 03 लाख रूपये की लागत से पचरी का निर्माण तथा वार्ड क्र. 24 जैन मंदिर के पीछे बुधवारी में राईटर पेंटर वेलफेयर एसोसिएशन आफ कोरबा के पास 05 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक भवन का अहाता निर्माण कार्य शामिल है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देशन में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के साथ कोरबा का भी तेजी से विकास हो रहा है।

उन्होने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुये कहा कि आप सबके आशीर्वाद से देश एवं प्रदेश में हमारी सरकार बनी तथा मुझे भी आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला, जिसके लिये मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ।

उन्होने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमारे छत्तीसगढ़ को सजाने, संवारने का काम कर रहे हैं, उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 वर्षो तक मुख्यमंत्री रहे डॉ.रमन सिंह ने राज्य को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाया तथा देश के अग्रणी राज्यों की कतार में छत्तीसगढ़ को खड़ा करने का कार्य किया, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में पुन: राज्य का तेजी से विकास हो रहा है।

मत्री श्री देवांगन ने कहा कि जहाँ तक कोरबा के विकास का प्रश्न है तो विगत ढाई वर्ष में कोरबा निगम क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें अनेक कार्य पूर्ण किये गये हैं, अनेक प्रगति पर हैं तथा शेष शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। उन्होने कहा कि कोरबा में 145 करोड़ रूपये से सड़कों का कायाकल्प किया जाना हैं, केवल बरसात खत्म होने का इंतजार है, जैसी ही बरसात खत्म होगी, सड़कों का कार्य तेजी से पूर्ण किया जायेगा।

इस अवसर पर कोरबा चन्द्रा समाज के पदाधिकारी लखन चन्द्रा एवं समाज के केन्द्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी चन्द्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह वायदा किया था कि 25 लाख रूपये से हमारे लिये भवन बनाया जायेगा, उन्होने जो वायदा किया था, वह आज पूरा हो चुका है। उन्होने कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का सदैव आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, जिसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

विष्णु भैया के सुशासन में महतारी वंदन बना महिलाओं की आत्मनिर्भरता का आधार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। विष्णु के सुशासन में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिन्हें प्रदेश की महिलाएं स्नेह से 'विष्णु भैया' कहती हैं, के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक संबल के साथ आत्मविश्वास और सम्मान का उजाला ला रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को परिवार की आवश्यकताओं में सहभागी बनने के साथ अपने निर्णय स्वयं लेने का भरोसा भी दे रही है।

ग्राम पंचायत लालपुर, विकासखंड गौरेला की श्रीमती नीलम राठौर के जीवन में भी महतारी वंदन योजना बदलाव की नई उम्मीद लेकर आई है। नीलम बताती हैं कि उन्हें योजना की 30वीं किस्त की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई है। नियमित रूप से मिलने वाली इस आर्थिक सहायता से वे अपनी और परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान दे पा रही हैं।

नीलम के लिए यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का आधार बन गई है। उनका कहना है कि पहले परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कई बार इंतजार करना पड़ता था।

अब महतारी वंदन योजना से नियमित सहायता मिलने के कारण वे अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के अनुसार पूरा कर पा रही हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में पहले से अधिक मजबूती के साथ भागीदारी निभा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे बढ़ा रही है।

आर्थिक सहयोग से बढ़ा आत्मविश्वास

नीलम बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि ने उनके भीतर आर्थिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ाया है। परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों में अपना योगदान देने से उन्हें यह महसूस होता है कि वे अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम होने से महिलाओं में अपने फैसले स्वयं लेने का भरोसा बढ़ता है। नियमित आर्थिक सहायता ने उन्हें भी अपने परिवार की जरूरतों को समझने, उन्हें प्राथमिकता देने और अपनी जिम्मेदारियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ निभाने का अवसर दिया है।

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से सरगुजा में बढ़ी ऊर्जा आत्मनिर्भरता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना सरगुजा जिले में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही आम परिवारों को बिजली खर्च से राहत दिलाने और ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना का लाभ लेकर अंबिकापुर के मायापुर निवासी श्रीमती नीधि वर्मा का परिवार अब बिजली खर्च के बोझ से मुक्त होकर सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। सोलर संयंत्र स्थापित होने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है।

श्रीमती नीधि वर्मा ने बताया कि सोलर संयंत्र स्थापित करने से पहले उनके घर में प्रतिमाह लगभग 4 से 5 हजार रुपये तक बिजली बिल आता था। बढ़े हुए बिजली खर्च से परिवार के बजट पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित कराने के बाद अब घरेलू बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो रही हैं और बिजली बिल लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि योजना ने परिवार को आर्थिक राहत देने के साथ बिजली की जरूरतों को पूरा करने का स्थायी और स्वच्छ विकल्प उपलब्ध कराया है।

श्रीमती वर्मा ने बताया कि योजना के तहत उन्हें लगभग 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी मिली। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सब्सिडी शामिल है। इस आर्थिक सहायता से सोलर संयंत्र स्थापित करने की लागत का बड़ा हिस्सा कम हुआ और उनके लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो गया। सौर ऊर्जा से मिलने वाले लाभ को साझा करते हुए श्रीमती नीधि वर्मा ने कहा कि पहले उनका परिवार केवल बिजली का उपभोक्ता था, लेकिन अब वे स्वयं बिजली का उत्पादन कर रहे हैं।

संरक्षित खेती और उद्यानिकी से किसान अनारथ साय ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ उद्यानिकी, संरक्षित खेती और फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर किसान अब आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाते हुए अपनी आय के नए स्रोत तैयार कर रहे हैं। जशपुर जिले के ग्राम पतराटोली के किसान श्री अनारथ साय ऐसे ही प्रगतिशील कृषक हैं, जिन्होंने उद्यानिकी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती को आर्थिक मजबूती का आधार बनाया है।

किसान अनारथ साय ने उद्यानिकी विभाग की योजना का लाभ लेते हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एक एकड़ क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित कर संरक्षित खेती की शुरुआत की है। इसमें वे ग्राफ्टेड टमाटर की आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं। संरक्षित वातावरण में फसल उत्पादन से बेहतर गुणवत्ता, मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा और उत्पादन प्रबंधन में सुविधा मिल रही है।

शेडनेट हाउस की स्थापना में कुल 28 लाख 40 हजार रुपए की लागत आई, जिसमें उद्यानिकी विभाग की ओर से 14 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। विभागीय सहयोग और आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसान ने खेती को नई दिशा दी है। अनारथ साय उद्यानिकी विभाग से लाभ लेकर ऑयल पाम की खेती भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन सहित विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं से मिले प्रोत्साहन ने उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर लाभकारी एवं दीर्घकालिक फसलों को अपनाने का अवसर दिया है।

ऑयल पाम जैसी फसल को अपनाकर किसान अपनी कृषि भूमि का बेहतर उपयोग कर रहे हैं और भविष्य के लिए स्थायी आय का आधार तैयार कर रहे हैं। किसान अनारथ साय ने समेकित उद्यानिकी विकास योजना के तहत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में आम एवं लीची का बगीचा भी विकसित किया है। फलदार पौधों की यह बागवानी उन्हें आने वाले वर्षों में निरंतर उत्पादन और आय का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने मुख्य उद्यानिकी फसलों के बीच उपलब्ध खाली भूमि का भी बेहतर उपयोग किया है। यही सोच उनकी खेती को एकीकृत एवं बहुआयामी बनाती है। श्री अनारथ साय ने बागवानी फसलों के बीच खाली स्थान का सदुपयोग करते हुए अंतरवर्ती खेती (इंटरक्रॉपिंग) को अपनाया है। वे स्ट्रॉबेरी, टमाटर और फूलगोभी जैसी फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं। इससे एक ओर भूमि का अधिकतम उपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग फसलों से अलग-अलग समय पर आय प्राप्त हो रही है। किसान का यह प्रयोग जशपुर के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है।

महलोई में विकास कार्यों को मिली नई सौगात, सामुदायिक कीर्तन भवन का भूमिपूजन और शेड का लोकार्पण

महलोई गांव में 104 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना से 205 महिलाओं को मिल रहा लाभः वित्त मंत्री ओपी चौधरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड अंतर्गत ग्राम महलोई में आज विकास कार्यों को नई गति मिली। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने ग्राम महलोई में 15.18 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक कीर्तन भवन का भूमिपूजन किया तथा उप स्वास्थ्य केंद्र के पास निर्मित शेड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांवों के विकास, गरीबों के कल्याण, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केवल महलोई गांव में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 104 हितग्राही हैं। इन गरीब परिवारों के आवास निर्माण के लिए सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में बड़ी संख्या में आवास निर्माण होने से निर्माण सामग्री और राजमिस्त्रियों की मांग भी बढ़ी है। गलियों में रेत, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री दिखाई दे रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दे रही है। उन्होंने बताया कि केवल महलोई गांव में 205 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है और अब तक उनके खातों में लगभग 52 लाख रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है और जो धान नहीं बेचते, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों की भी सरकार ने चिंता की है। ऐसे परिवारों को भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं और मजदूरों के हित में संचालित योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा।

श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ के साथ-साथ पुसौर क्षेत्र को भी एक महत्वपूर्ण विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि आसपास के गांवों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।

पुसौर में रजिस्ट्री कार्यालय शुरू होने से लोगों को रजिस्ट्री संबंधी कार्यों के लिए रायगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्होंने बताया कि युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायगढ़ के साथ पुसौर में भी नालंदा परिसर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा पुसौर में जिला अस्पताल के स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े अस्पताल की स्थापना की जा रही है। क्षेत्र की बेटियों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुसौर में नर्सिंग कॉलेज भी खोला जा रहा है।

वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि ग्राम महलोई में 15 लाख 18 हजार रुपये की लागत से सामुदायिक कीर्तन भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भवन का उपयोग ग्रामीण कीर्तन, भजन, भागवत कथा, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के साथ-साथ युवाओं के कार्यक्रमों के लिए भी कर सकेंगे। इससे ग्रामीणों को कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अलग से टेंट आदि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी।

प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड में बड़ी छलांग

अब ऑस्कर विजेता रसेल क्रो के साथ मचाएंगी धमाल

ऑस्कर विजेता अभिनेता रसेल क्रो और प्रियंका चोपड़ा आगामी साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लूफ्लाई में एक साथ नजर आने वाले हैं। प्रेडेटर्स और सुपरहिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में अपनी छाप छोड़ चुके जाने-माने निर्देशक निमरॉड एंटल इस बड़े बजट की फिल्म का निर्देशन करेंगे। हॉलीवुड की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में प्रियंका और रसेल की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ एक्शन और रोमांच का तड़का लगाती दिखेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खरीददारों के सामने पेश किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग इसी साल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में शुरू होगी।

इसकी कहानी संयुक्त राष्ट्र के एक दुखी अनुवादक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे कांगो में एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। उसका काम एक ऐसे रहस्यमयी विमान को ढूंढना है, जिसका अस्तित्व ही दुनिया से छिपा हुआ था।

3 लेखकों द्वारा लिखित इस फिल्म के निर्माण की कमान 6 निर्माताओं की टीम संभाल रही है, जबकि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हाइलैंड फिल्म ग्रूप देखेगा।

ग्रूप की सीईओ एरियन फ्रेजर ने कहा, ब्लूफ्लाई में रसेल क्रो और प्रियंका चोपड़ा जोनास जैसे शानदार कलाकार हैं। ये डेनिस विलेन्यूवे की फिल्म अराइवल की तरह ही गहरी भावनाओं और भारी जोखिम से भरी एक बेहतरीन साइंस-फिक्शन थ्रिलर है। हम दुनियाभर के खरीदारों के सामने इस प्रोजेक्ट को पेश करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

निर्देशक निमरॉड एंटल ने कहा, ब्लूफ्लाई एक बेहद रोमांचक और दमदार किरदारों वाली थ्रिलर फिल्म है, जो साहसिक साइंस-फिक्शन पर आधारित है। ये ठीक वैसी ही वास्तविक, रहस्यमयी और तनावपूर्ण ऊिल्म है, जैसी मुझे पसंद है। इससे बेहतर स्टारकास्ट और टीम नहीं मिल सकती थी।

निमरॉड एंटल एक प्रसिद्ध हंगेरियन-अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक और अभिनेता हैं। उन्हें हॉलीवुड की चर्चित साइंस-फिक्शन और एक्शन फिल्मों जैसे प्रेडेटर्स, वेकेंसी और सुपरहिट टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के निर्देशन के लिए जाना जाता है।

रसेल पिछली बार फिल्म न्यूरेमबर्ग में नजर आए थे और अब उनके पास हाइलैंडर जैसी बड़ी फिल्में हैं।

उधर प्रियंका भी लगातार नए प्रोजेक्ट्स के साथ अपने हॉलीवुड करियर का विस्तार कर रही हैं। उनकी इस यात्रा में ब्लूफ्लाई एक और बड़ा और अहम अध्याय जोडऩे जा रही है, जो उनके प्रशंसकों के लिए काफी खास होने वाला है। प्रियंका निर्देशक एसएस राजामौली की पैन इंडिया फिल्म वाराणसी से भारतीय सिनेमा में भी अपनी धमाकेदार वापसी करने को तैयार हैं।

फिल्म मैं वापस आऊंगा ने ओटीटी पर दी दस्तक, नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम

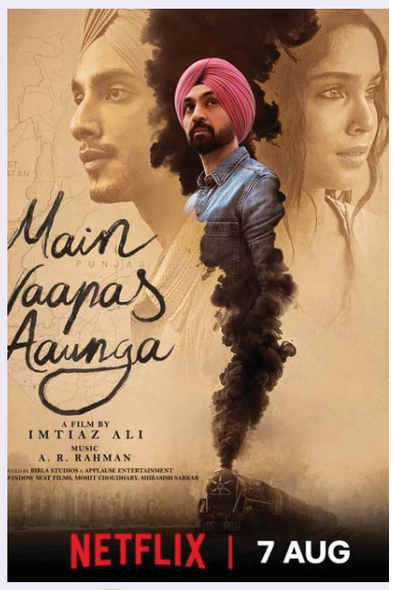

निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने आ गई है। दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारों से सजी ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने विश्व स्तर पर 90 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था। सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने के बाद फिल्म का प्रीमियर ओटीटी पर कर दिया गया है, जिससे लोग घर बैठकर इसका लुत्फ उठा सकेंगे।

नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर मैं वापस आऊंगा की ओटीटी रिलीज तारीख का ऐलान कर बताया कि फिल्म 7 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी जाएगी। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है।

इसकी कहानी भारत-विभाजन (1947) के समय एक अधूरी प्रेम-कहानी और वर्तमान में एक बीमार दादा की देखभाल कर रहे उसके पोते के बीच के गहरे भावनात्मक रिश्ते पर आधारित है।

कौन हैं चार्ली चौहान? एक्ट्रेस ने भारतीय क्रिकेटर रामनदीप सिंह से रचाई शादी

चार्ली चौहान और रामनदीप सिंह की शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखते ही फैंस खुश हो गए। चार्ली और रामनदीप पारंपरिक कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रहे थे और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत पर फैंस और सेलेब्स ने जमकर बधाइयां दीं।

चार्ली चौहान टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम हैं। उन्हें 'कैसी ये यारियां', 'बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर?' और 'एमटीवी रोडीज' जैसे शोज से पहचान मिली। इनके अलावा चार्ली एमटीवी रोडीज सीजन 7 में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आईं थीं और नच बलिए का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने 'ये है आशिकी 4' में इनारा का किरदार भी निभाया था। इसके अलावा वे कुछ शॉर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

लिरिसिस्ट भी हैं चार्ली

चार्ली एक्टिंग ही नहीं बल्कि राइटिंग में भी रुची रखती हैं और लिरिसिस्ट भी हैं। वो बेपरवाहियां म्यूजिक एल्बम का हिस्सा भी रही हैं। अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के दम पर उन्होंने मजबूत फैन फॉलोइंग बनाई है।

सादगी भरी खूबसूरत शादी

जहां ज्यादातर सेलेब्रिटी शादियां अपने भव्य अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं, वहीं चार्ली चौहान और रामनदीप सिंह ने सादगी और प्राइवेट तरीके से शादी करने का फैसला लिया। शादी बहुत ही खास और भावनात्मक रही, जिसमें सिर्फ अपने लोग ही शामिल थे।

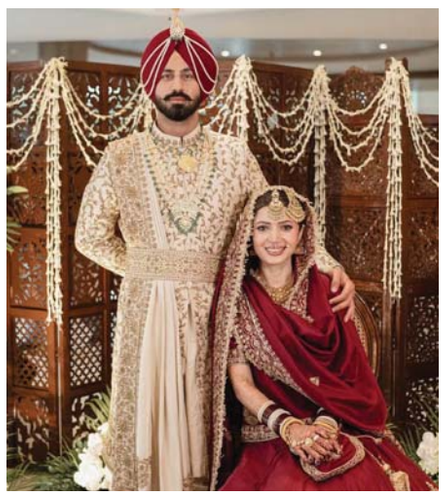

हॉट अवतार में दिखीं 'द केरल स्टोरी 2' की यह एक्ट्रेस....

एक्ट्रेस उल्का गुप्ता अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उल्का काफी समय से सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अब उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके बाद फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं।

उल्का गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों की पोस्ट शेयर की, जिसमें वो काफी शानदार दिख रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'मिट्टी जैसे रंगों में सजी, हर एक अंदाज़ को अपनाते हुए।

पोस्ट में उल्का ब्राउन कलर की ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी बोल्ड लुक में अदाएं बिखेरती नजर आ रही हैं। अब जहां एक तरफ कई फैंस उनके इस लुक की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके इस फोटोशूट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

एक यूजर ने कमेंट किया- 'मेरी फेवरेट थी, पर अब नहीं।' वहीं दूसरे ने लिखा- 'आपका ट्रेडिशनल में पिछला लुक ज्यादा अच्छा था।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- 'आप इस तरह के शूट क्यों करवाती हैं।' इनके अलावा कई लोगों ने उनके लुक की तारीफ भी की।

बता दें कि उल्का गुप्ता हाल ही में 'केरल स्टोरी 2' में नजर आईं थीं, जो 'केरल स्टोरी' का सीक्वल था। 'केरल स्टोरी 2' बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, हालांकि उल्का की एक्टिंग को काफी सराहना मिली थी।

उल्का गुप्ता पहली बार टीवी सीरियल 'झांसी' की रानी में मुख्य भूमिका में नजर आई थीं। हिंदी टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उल्का ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। उल्का की पहली तेलुगु फिल्म 2015 में 'आंध्र पोरी' नाम से रिलीज हुई थी। उल्का गुप्ता ने रणवीर सिंह की 'सिम्बा' में भी अभिनय किया था। उल्का को अपने उम्दा अभिनय के लिए कई टीवी अवॉर्ड भी मिल चुके हैं।

सावन के दौरान एयर फ्रायर में बनाएं ये व्यंजन, तुरंत हो जाएंगे तैयार

हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व है। इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान खाने-पीने का खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी सावन के दौरान व्रत रखते हैं और रोजाना क्या खाएं? इस सवाल से परेशान रहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे एयर फ्रायर व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना मुश्किल नहीं है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

आलू के चिप्स

सबसे पहले आलू को छीलकर पतले-पतले काट लें, फिर इन्हें पानी में भिगोकर रख दें।

इसके बाद इनसे अतिरिक्त पानी निकालकर इन्हें एक कटोरे में डालें और इसके साथ सेंधा नमक, काली मिर्च और देसी घी मिलाएं। अब आलू के टुकड़ों को एयर फ्रायर में डालकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए पकाएं।

इसके बाद आलू के चिप्स को एक कटोरे में निकालकर इनमें थोड़ा नींबू का रस डालकर इन्हें परोसें।

साबूदाने के ढोकले

सबसे पहले साबूदाने को 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगोएं, फिर भीगे हुए साबूदाने को एक बर्तन में डालकर पीस लें। अब मिश्रण को एक कटोरे में डालकर उसमें अदरक का पेस्ट, सेधा नमक और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को 2-3 मिनट के लिए फेंटे।

अब मिश्रण को एक घी लगे बर्तन में डालकर एयर फ्रायर में 15 मिनट के लिए रखें। आखिर में ढोकले पर सरसों का तड़का लगाकर इसे परोसें।

साबूदाना टिक्की

इसके लिए सबसे पहले साबूदाना, आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सेंधा नमक और नींबू के रस को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर इन्हें एयर फ्रायर में रखें। इसके बाद इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद गर्मागर्म टिक्कियों को बाहर निकालकर इन्हें परोसें। इस तरह की टिक्कियां स्वादिष्ट होती हैं और व्रत के लिए उपयुक्त भी।

शकरकंद के चिप्स

सबसे पहले एयर फ्रायर को पहले से गर्म करें, फिर उसमें छिली और पतली कटी हुई शकरकंद, स्वादानुसार सेंधा नमक, थोड़ा तेल और काली मिर्च पाउडर डालकर 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रखें।

इसके बाद शकरकंद के चिप्स को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, फिर इन्हें किसी डिब्बे में भरकर रख लें। यह एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है।

अमीषा पटेल बोलीं- कभी नहीं करूंगी शादी एक मर्द को संभालना मेरे बस की बात नहीं

अभिनेत्री अमीषा पटेल ने हाल ही में एक्स पर अपने आस्कएमी सेशन के दौरान शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया। जब एक फैन ने उनसे शादी की योजना के बारे में पूछा तो अमीषा ने दोटूक जवाब देते हुए कहा कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। 49 वर्षीय अभिनेत्री ने बताया कि वो सिंगल रहकर बेहद खुश हैं और उनके पास 100 से अधिक करीबी दोस्त और परिवार हैं जो उनसे प्यार करते हैं।

एक्स पर एक फैन ने उनसे पूछा, आप शादी कब कर रही हैं? अमीषा का जवाब सीधा और साफ था। उन्होंने लिखा, कभी नहीं। मैं अकेले रहकर बेहद खुश हूं। मेरे पास प्यार करने वाले 100 करीबी दोस्त और परिवार हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी आकर ये सब कुछ बदल दे। ये जोखिम मैं नहीं उठा सकती।

अमीषा ने अब पूरी तरह साफ कर दिया है कि वो कभी शादी के बंधन में नहीं बंधने वाली हैं।

रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने बताया था कि उन्होंने अपना एक गंभीर रिश्ता इसलिए तोड़ दिया था, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में काम करें।

अमीषा ने कहा, जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वे आपके करियर को आगे बढऩे देंगे। मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ खोया है और प्यार के लिए भी बहुत कुछ कुर्बान किया है। मैंने दोनों के लिए फैसले लिए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है।

हालांकि, तब अमीषा ने बताया था कि उन्होंने शादी के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था, अगर मुझे कोई सही इंसान मिलता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। मुझे आज भी कई बड़े परिवारों से रिश्ते आते हैं और मेरी उम्र से आधे लड़के भी डेट पर ले जाना चाहते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि इंसान का मानसिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है। मुझसे बड़े कई लोगों का दिमाग मक्खी जैसा होता है। बता दें कि अमीषा का सबसे चर्चित रिश्ता निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ रहा। शादीशुदा विक्रम के साथ 5 साल लिव-इन में रहने के कारण उनका घरवालों से भी विवाद हुआ, हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए। अगर काम की बात करें तो 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद अमीषा ने साल 2023 में सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 से पर्दे पर धमाकेदार वापसी की थी।

अम्बेडकर अस्पताल की इमरजेंसी सेवा में बदली मरीजों की एंट्री व्यवस्था, गंभीर मरीजों को सीएमओ कक्ष से मिलेगा सीधा प्रवेश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के आपात चिकित्सा विभाग में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब गंभीर मरीजों को इमरजेंसी तक पहुंचने के लिए भीड़ के बीच से गुजरने की जरूरत नहीं होगी।

मरीजों की सुविधा, सुगम आवाजाही और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने आपात चिकित्सा विभाग की प्रवेश एवं पंजीयन व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत ओपीडी गेट स्थित कक्ष क्रमांक 100, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) कक्ष से आपात चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों का प्रवेश एवं पंजीयन किया जाएगा। सीएमओ कक्ष में मरीज की प्रारंभिक जांच के बाद गंभीर एवं तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों को बिना अनावश्यक विलंब के सीधे आपात चिकित्सा विभाग में भेजा जाएगा। इससे गंभीर मरीजों को इमरजेंसी तक पहुंचने में आसानी होगी और मरीजों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व तक आपात चिकित्सा विभाग का संचालन इसी स्थान से किया जाता था। मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण वर्तमान प्रवेश व्यवस्था में स्थानभाव के कारण भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही थी। इससे मरीजों एवं उनके परिजनों को आवागमन में असुविधा हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पूर्व निर्धारित प्रवेश एवं पंजीयन स्थल को पुनः व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है।

अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी के अनुमोदन के उपरांत अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर की अध्यक्षता में शनिवार को अधीक्षक कक्ष में आपात चिकित्सा विभाग में मरीजों के सुचारू आवागमन एवं चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। अस्पताल के राउंड के दौरान आपात चिकित्सा विभाग में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न भीड़ एवं स्थानाभाव का निरीक्षण किया गया। इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों के साथ चर्चा कर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया।

डॉ. संतोष सोनकर के अनुसार, नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करना, गंभीर मरीजों को तत्काल आपात चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना तथा मरीजों एवं उनके परिजनों के आवागमन को सुगम बनाना है। पंजीयन एवं प्रवेश व्यवस्था में परिवर्तन के दौरान आपातकालीन सेवाओं की निरंतरता को प्राथमिकता दी जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों के आवागमन एवं पंजीयन व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो मरीजों की सुविधा के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।

खास-खबर

कृषि विज्ञान केन्द्र सुरगी की मौसम आधारित विशेष सलाह

राजनांदगांव। कृषि विज्ञान केन्द्र सुरगी द्वारा किसानों को मौसम आधारित कृषि से संबंधित समसामयिक सलाह दी गई है। जिले एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में लगभग सभी खरीफ फसलों की रोपाई एवं बोआई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्तमान फसल अवधि लगभग 20 -25 दिनों की हो चुकी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में घने बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम वर्षा होने की संभावना है। किसानों को निरंतर वर्षा की स्थिति में निंदानाशक का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी गई है। धान पर संकरी तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु धान की बुवाई के 20-25 दिन के अंदर 15 लीटर क्षमता वाले स्प्रेयर में 25 स्प्रेयर उपयोग करने तथा आवश्यकतानुसार खरपतवारनाशी जैसे-बिसपायरिबेक सोडियम 200-250 ग्राम प्रति हेक्टेयर में का छिड़काव करें। अरहर एवं सोयाबीन फसल वृद्धिकाल अवस्था में है। संकरी एवं चौड़ी पट्टी वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु बुआई के 18- 20 दिनों तक आवश्यकतानुसार खरपतवारनाशी जैसे- एमेजाथाईपर 10 प्रतिशत एसएल 750 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें।

राष्ट्रीय स्तर पर बेमेतरा का गौरव बढ़ाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान

बेमेतरा। राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्टबाल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बेमेतरा जिले का नाम रोशन करने वाले दो प्रतिभावान खिलाड़ियों प्रिंस सिंह एवं आशीष पाटिल का आज कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने सम्मान किया। दोनों खिलाड़ियों ने सॉफ्टबाल खेल में छत्तीसगढ़ राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर राज्य शासन द्वारा उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। सम्मान के दौरान कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जिले के युवा खिलाड़ियों द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पूरे जिले के लिए गौरव की बात है।

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्टजनों को किया सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम यहां राजधानी रायपुर के महोबा बाजार स्थित एक निजी होटल में आयोजित युवा मंच कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब छत्तीसगढ़ समन्वित रूप से प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक पूरे प्रदेश के लक्ष्यकेंद्रित विकास के लिए सरकार संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्टजनों सम्मानित किया।

युवा मंच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बड़ी बाधा थी। हमारी सरकार के गठन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद विषय पर हुई बैठक में यह तथ्य हमारे सामने आया कि देश में शेष नक्सल समस्या का अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही था। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति से एक डेडलाइन तय हुई और हमारे सुरक्षाबल के जवानों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बना दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है। धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया है। वहाँ बम्बू राफ्टिंग जैसी पर्यटन गतिविधियां संचालित हैं और होम स्टे में पर्यटक आकर रुक रहे हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई उद्योग नीति में पर्यटन को भी शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में धर्मांतरण रोकने सबसे सख्त कानून लाने वाला प्रदेश है। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर अब कड़ी कार्यवाही की जा रही है। अन्य प्रदेशों के कानूनों का विस्तार से अध्ययन करके छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंर्त्य बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएससी में भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अब पीएससी से लेकर सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हो रही हैं और युवाओं के साथ उनके अभिभावक भी अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर निश्चिंत हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार युवाओं से लगातार संवाद कर रही है। उनके सभी सुझावों का स्वागत है। युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। विकास की नीति निर्माण में युवाओं के सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई ने जनजातीय विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में छत्तीसगढ़ के 6 हजार गांवों को शामिल किया गया है। हमारे प्रदेश में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनके उत्थान के लिए हम कटिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा विकास का मूलमंत्र है। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर स्कूल संचालित हैं। हर ब्लॉक में कॉलेज हैं। बस्तर के नक्सलमुक्त होने के बाद वहां एजुकेशन सिटी बनायी जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।राज्य में शिक्षा मिशन पर भी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती राज्यों में भी आदिवासी बहुलता है, इसे देखते हुए हमारा प्रयास है कि राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी स्थापित हो। जिसका लाभ इस क्षेत्र के जनजातीय बच्चों को मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पांच नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिल गई है। जिनमें कुल 250 सीटें स्वीकृत हुई हैं और इसी वर्ष से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया पौधारोपण, बोले हरियाली बढ़ेगी तो पर्यावरण भी स्वस्थ और सुंदर बनेगा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ द्वारा आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में अमरूद का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण की अनमोल धरोहर हैं। पौधारोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की देखभाल और उनका संरक्षण भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण तैयार कर सकते हैं। हरियाली बढ़ेगी, तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ और सुंदर बनेगा।

उन्होंने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ द्वारा आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों और युवाओं की पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भागीदारी से इस अभियान को और व्यापक स्वरूप दिया जा सकता है।

कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ललित प्रकाश पटैरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में बोले तकनीकी शिक्षा मंत्री पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू होंगे एआई पाठ्यक्रम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक एवं शासकीय सह-शिक्षा पॉलिटेक्निक, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास, नवाचार, उद्यमिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विशेष बल दिया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि राज्य शासन आगामी शैक्षणिक सत्र से पॉलिटेक्निक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ढ्ढ) से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रयासरत है। मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यावहारिक कौशल और नवाचार ही सफलता का आधार हैं। उन्होंने राज्य शासन द्वारा संचालित आई-हब और नई औद्योगिक नीति का उल्लेख करते हुए युवाओं से स्टार्टअप व स्वरोजगार के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का आयोजन 01 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नए विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा, संस्थागत संस्कृति, नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व विकास से परिचित कराना है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अतिरिक्त संचालक डॉ. अमिताभ दुबे ने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने और अनुशासन के साथ लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया।

लोहाखान में विकास कार्यों को मिली नई सौगात, आंगनबाड़ी भवन, मंगल भवन और अतिरिक्त कक्ष का होगा निर्माण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लोहाखान में विकास कार्यों को नई गति मिली है। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने ग्राम लोहाखान में आंगनबाड़ी भवन, मंगल भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक, शैक्षणिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांवों के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवन के निर्माण से गांव के बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मंगल भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। अतिरिक्त कक्ष के निर्माण से संबंधित संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, नाली, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दिलाकर पूरा कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन को सुविधाजनक बनाना और गांवों में अधोसंरचना को मजबूत करना है।

देवलसुर्रा में विकास कार्यों को मिली नई गति, आंगन-बाड़ी भवन और सांस्कृतिक मंच का हुआ भूमिपूजन

आगामी पांच वर्षों में पिछले 20-25 वर्षों से अधिक विकास कार्य कराने का संकल्प

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड अंतर्गत ग्राम देवलसुर्रा में विकास कार्यों को नई गति मिली है। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने ग्राम देवलसुर्रा में आंगनबाड़ी भवन एवं सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक विकास की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख गरीब परिवारों के पक्के आवास निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिल रही है। देवलसुर्रा गांव में ही करीब 180 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है और अब तक लगभग 48 लाख रुपये की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा चुकी है। इसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

मंत्री चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में वर्षों से उपेक्षित सिंचाई संरचनाओं के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी जा रही है। बड़े हरदी, पुसौर क्षेत्र, बाघाडोला, बासनपाली, सोड़ेकेला, सीहा और टिनमिनी सहित विभिन्न स्थानों पर सिंचाई टैंकों के जीर्णोद्धार के कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों से किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि देवलसुर्रा पंचायत के लिए एनटीपीसी प्रबंधन के सहयोग से एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत कराए गए हैं। इनमें देवलसुर्रा गांव में 20 लाख रुपये के विकास कार्य भी शामिल हैं। इन कार्यों की स्वीकृति के लिए उनके कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन एवं एनटीपीसी प्रबंधन के साथ लगातार समन्वय किया गया।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि पुसौर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए पुसौर में नालंदा परिसर विकसित किया जा रहा है। वहीं रजिस्ट्री संबंधी कार्यों के लिए क्षेत्रवासियों को अब रायगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुसौर में ही रजिस्ट्री कार्यालय शुरू हो चुका है।

देवलसुर्रा में कई अन्य विकास कार्य भी होंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी भवन और सांस्कृतिक मंच निर्माण के साथ-साथ देवलसुर्रा में अन्य विकास कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं। इनमें लगभग 5.93 लाख रुपये की लागत से ह्यूम पाइप कल्वर्ट निर्माण, करीब 2.40 लाख रुपये की लागत से बोर एवं सिंचाई पंप निर्माण, गोटिया पारा से नीचे तालाब तक आरसीसी नाली निर्माण, बीज बस्ती एवं विंध्यवासिनी चौक के पास शेड निर्माण, करीब 12.10 लाख रुपये की लागत से उचित मूल्य दुकान निर्माण तथा प्राथमिक शाला में लगभग 4 लाख रुपये की लागत से किचन शेड निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

टमाटर की खेती से भारती की बढ़ी आमदनी

रायपुर। महासमुंद जिले के अंतर्गत ग्राम गोंडपाली की महिला कृषक भारती बंसल ने परंपरागत धान की खेती से आगे बढ़कर आधुनिक उद्यानिकी फसल ग्राफ्टेड टमाटर की खेती को अपनाकर अपनी कृषि आय में वृद्धि की है। स्नातक शिक्षित कृषक श्रीमती भारती वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक ग्राफ्टेड बैगन टमाटर सीडलिंग प्रदर्शन के तहत नवीन तकनीक से टमाटर की खेती कर रही है। श्रीमती भारती बताती हैं कि उनके पास कुल 0.40 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। पूर्व में उनके द्वारा परंपरागत रूप से धान की खेती की जाती थी। धान की खेती में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के साथ ही लागत भी अधिक आती थी। भारती बंसल ने धान के स्थान पर ग्राफ्टेड टमाटर की खेती अपनाने का निर्णय लिया।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

पर्यटन स्थलों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की सख्ती

गरियाबंद। जिले के पर्यटन स्थलों पर शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ गरियाबंद पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर- के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी अभियान के तहत-चिंगरापगार तिराहा- के पास विशेष चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहन चालकों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस टीम ने आने-जाने वाले वाहन चालकों का -ब्रीथ एनालाइजर मशीन से अल्कोहल टेस्ट- किया। जांच में तीन मोटरसाइकिल चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने तीनों वाहन चालकों के खिलाफ -मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185- के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर संबंधित वाहनों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन स्थलों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ -सख्त चेकिंग और वैधानिक कार्रवाई का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

पेंटिंग के लिए दी इनोवा का इंजन बदलने का आरोप, दो पर एफआईआर

रायपुर। खम्हारडीह थाना क्षेत्र में ग्राहक की इनोवा कार का इंजन कथित तौर पर बदलने के मामले में पुलिस ने गैराज संचालक समेत दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। सेकेंड हैंड कार कारोबारी ड्रीम कार वर्ल्ड अमलीडीह के संचालक सन्नी बीरे की शिकायत पर पुलिस ने हेमंत विश्वकर्मा और जयदीप सिंह के खिलाफ गबन के आरोप में धारा 316 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होगा कि वाहन का इंजन बदलने के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, दूसरे वाहन का इंजन वहां कैसे पहुंचा और पूरे मामले में दोनों आरोपियों की क्या भूमिका रही।

हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बाकारूमा रेंज के ग्राम जमावीरा निवासी रतन गुप्ता उर्फ चंदन (60) शनिवार रात करीब 2 बजे घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान जंगल की ओर से एक हाथी बस्ती के पास पहुंच गया। अचानक हाथी से सामना होने पर उसने रतन गुप्ता पर हमला कर दिया। हमले में सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाथी कुछ देर बाद वापस जंगल की ओर लौट गया। ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

त्योहारी सीजन से पहले ट्रैफिक पुलिस की सख्ती : राजनांदगांव में 1035 वाहनों पर कार्रवाई

श्रीकंचनपथ समाचार

राजनांदगांव। राजनांदगांव यातायात पुलिस ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर चलाए गए अभियान में 1,035 वाहनों पर कार्रवाई कर 5 लाख 26 हजार 300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस टीमों ने नया बस स्टैंड चौक, महावीर चौक, खैरागढ़ रोड, रेलवे स्टेशन रोड, गंज चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, मानव मंदिर चौक, फव्वारा चौक, सदर लाइन, मोतीपुर अंडरब्रिज और सर्विस रोड समेत शहर के प्रमुख और व्यस्त स्थानों पर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने वाले 556 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की

गई। पुलिस ने वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थल का इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 18 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने त्योहारी सीजन के दौरान नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती जारी रखने की बात कही है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने वाले 29 चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वहीं, प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 3 वाहनों से 9 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 429 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करने की अपील की है।

रायपुर में विवाद के बाद युवक की हत्या इलाज के दौरान मौत, दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजधानी रायपुर के सतनामी पारा कोटा में आपसी विवाद के बाद एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने मृतक का नाम महेश धृतलहरे और आरोपियों का नाम तुषार महिधर उर्फ बाउ (19) और सुरेन्द्र मधुकर उर्फ पोका (25) बताया है।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल लकड़ी और ईंट भी जब्त की गई है। यह मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, 7-8 अगस्त की दरम्यानी रात करीब 12.20 बजे सतनामी पारा कोटा में बलदाउ के घर के पीछे महेश के साथ मारपीट की गई।

हमले में उसके सिर, गर्दन और सीने पर गंभीर चोटें आईं। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महेश के भाई राजेन्द्र धृतलहरे ने पुलिस को बताया कि घटना की रात वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी दौरान करीब 12.30 बजे मोहल्ले का बल्लू रात्रे उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर कहा कि महेश को बचा लो।

इसके बाद राजेन्द्र अपने भाई दिनेश के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। मौके पर महेश गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा मिला। परिजनों ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि तुषार महिधर उर्फ बाउ और सुरेन्द्र मधुकर उर्फ पोका ने उसके साथ मारपीट की है। महेश के सिर पर गंभीर चोट थी। हालत बिगड़ने के कारण वह ज्यादा बातचीत नहीं कर सका और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।

पुलिस ने कुछ घंटों में दोनों को पकड़ा

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने आपसी विवाद के चलते महेश के साथ मारपीट करने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल लकड़ी और ईंट जब्त की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

ट्रांसफार्मर पार्ट्स और केबल चोरी, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायगढ़। रायगढ़ के एसइसीएल छाल उपक्षेत्र की धरमखदान में चोरों ने करीब 1.20 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। आरोपियों ने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, केबल, पानी पंप के पार्ट्स और लोहे के पाइप चोरी करने के साथ ट्रांसफार्मर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान और 3 बाइक बरामद की है। मामला छाल थाना क्षेत्र का है। छाल उपक्षेत्र के सुरक्षा प्रहरी दिलीप कुमार राठिया ने शुक्रवार को छाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे से 11 बजे के बीच धरमखदान में लगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, ट्रांसफार्मर केबल, पानी पंप के पार्ट्स और लोहे के पाइप चोरी कर लिए गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 1 लाख 20 हजार रुपए बताई गई। घटना के दौरान ट्रांसफार्मर को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खेदापाली चौक के पास कुछ संदिग्ध लोग लोहे के पाइप, ट्रांसफार्मर केबल और अन्य लोहे का सामान बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर 6 संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान दीपक पात्रो (42), कोरबा, शनिचराम अरमु (22), छतन धनवार (28), रूपभवन सिंह उइके (28), टुपाल सिंह मरावी (23) और भारत सिंह मरकाम के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में संगठित अपराध से संबंधित धारा 112(2) और 3(5) बीएनएस भी जोड़ी।

सीमेंट पाइप के अंदर मिला लापता युवक का शव, हत्या की आशंका

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजधानी रायपुर के रावाभाठा मैदान में शनिवार को 23 वर्षीय युवक की लाश मिली। युवक पिछले तीन दिनों से लापता था और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। मृतक की पहचान पवन टंडन के रूप में हुई है। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है।

परिजनों के मुताबिक, पवन 5 अगस्त से लापता था। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका था। शनिवार को स्थानीय लोगों ने मैदान में युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी।

जानकारी मिलते ही खमतराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्नस्रुटीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही युवक के पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की जानकारी भी जुटा रही है।

युवक का शव मिलने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शव को सीमेंट पाइप के अंदर छिपाए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी मौत की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पवन आखिरी बार किन लोगों के साथ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

सूने मकान से 60 लाख की चोरी करने वाले गिरफ्तार

सोने-चांदी के जेवर और कैश ले गए थे आरोपी, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ाए चोर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजधानी रायपुर के अरिहंत नगर सरोना में सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 60 लाख रुपए की चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी घर की आलमारी का लॉकर तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान ले गए थे।

पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का पूरा माल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है। दोनों आरोपी पहले भी चोरी और मारपीट के मामलों में जेल जा चुके हैं। यह मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है।

अरिहंत नगर के रहने वाले रविकांत गुप्ता 28 जुलाई को घर में ताला लगाकर परिवार के साथ बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए।

इसके बाद आलमारी का लॉकर तोड़कर जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। शिकायत पर आमानाका पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

इस तरह पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू की।

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की हजारों रिकॉर्डिंग खंगाली गई। फुटेज में संदिग्ध लोगों और वाहनों की आवाजाही की जानकारी जुटाकर उनकी जांच की।

साथ ही पुराने चोरी के मामलों में शामिल आरोपियों और हाल ही में जेल से बाहर आए संदिग्धों की जानकारी जुटाई गई। जांच से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने करण तांडी उर्फ केडे (21) और लक्ष्मी नारायण गोस्वामी उर्फ मोंटी (19) को गिरफ्तार किया।

पहले करते रहे इनकार, फिर कबूली चोरी

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने शुरुआत में वारदात में शामिल होने से इनकार किया और टीम को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि, सबूतों के आधार पर पूछताछ करने पर दोनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य चोरी का सामान, साथ ही घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई गई है।

आदतन अपराधी हैं आरोपी

पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पंडरी थाने में पहले से चोरी और मारपीट के मामले दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि आरोपी लक्ष्मी नारायण के खिलाफ 12 जुलाई को दुबे कॉलोनी स्थित बालाजी मेडिकल कॉलेज कैंपस में एसी के कॉपर वायर चोरी का मामला भी दर्ज हुआ था। इस केस के बाद से वह फरार चल रहा था। अब पुलिस इस मामले में भी उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी।

कर्ज की किश्त-ब्याज को लेकर विवाद में मारपीट, 2 महिलाएं गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र के कोहका में कर्ज की किश्त और ब्याज को लेकर हुए विवाद के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों महिलाएं एक महिला के घर पहुंचीं और उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट की। इसके बाद घर से एक्टिवा, वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन ले गईं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर तीनों सामान बरामद कर लिए हैं।

कृपाल नगर, सड़क नंबर-6, कोहका निवासी बलजीत कौर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने सीमा यादव से अलग-अलग समय पर रुपए उधार लिए थे। रकम के बदले सुरक्षा के तौर पर बैंक के चेक और हस्ताक्षरित स्टाम्प दिए गए थे। बलजीत कौर का आरोप है कि उन्होंने किश्तों में रकम चुकाई, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के तौर पर दिए गए चेक उन्हें वापस नहीं किए गए।

किश्त और ब्याज को लेकर घर पहुंचीं दोनों महिलाएं

शिकायत के मुताबिक, 19 जुलाई 2026 को सीमा यादव और बबली साहू बलजीत कौर के घर पहुंचीं। यहां कर्ज की किश्त और ब्याज की रकम को लेकर विवाद हो गया। बलजीत कौर ने आरोप लगाया कि दोनों महिलाओं ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। साथ ही उन्हें धमकी भी दी गई। इसके बाद उनके घर से पति के नाम पंजीकृत एक्टिवा वर्लपूल कंपनी की वॉशिंग मशीन और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन ले जाया गया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला सामान बरामद

शिकायत के आधार पर सुपेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 1138/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(2), 308(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए।

एक्टिवा, वॉशिंग मशीन और मोबाइल जब्त

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की निशानदेही पर महिला के घर से ले जाए गए सामान को अलग-अलग स्थानों से बरामद किया गया। पुलिस ने एक्टिवा, वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन को विधिवत जब्त कर लिया है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सीमा यादव (36), निवासी वैशाली नगर और बबली साहू (44), निवासी शिक्षित नगर, कोहका को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

चेक और दस्तावेज रखने की भी जांच

पुलिस के अनुसार, मामले में यह आरोप भी सामने आया है कि उधार रकम देते समय सुरक्षा के तौर पर चेक और हस्ताक्षरित दस्तावेज रखे गए थे। किश्त में देरी होने पर कथित तौर पर अतिरिक्त राशि की मांग और दबाव बनाने की बात भी सामने आई है।

विवाद के दौरान सामान अपने कब्जे में लेने के आरोप की भी जांच की जा रही है। प्रकरण में कर्जा/साहूकारी संबंधी अधिनियम की धारा-4 का भी जिक्र है। इस संबंध में अंतिम स्थिति मूल अपराध अभिलेख और जांच के आधार पर स्पष्ट होगी।

बस्तर मेले में युवक पर जानलेवा हमला सात महीने बाद दो आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर मेले में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने करीब 7 महीने से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक की आंखों में मिर्च पाउडर डालने के बाद डंडे से सिर और पैर पर हमला किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल बांस का डंडा भी बरामद किया है।

मामला बस्तर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, छापर भानपुरी निवासी छोटू कश्यप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसका भाई सूरज कश्यप (22) का आरोपियों के साथ मेले में विवाद हुआ था। इसी पुरानी रंजिश को लेकर 30 जनवरी 2026 को बस्तर मेले के दौरान भाटीपारा चौक में आरोपियों ने सूरज को घेर लिया।

आरोपी देवा बघेल ने अपने साथियों को बुलाया और सूरज की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडे से उसके सिर, पैर पर हमला किया। हमले में सूरज को गंभीर चोटें आईं। तत्काल

उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद बस्तर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 18/2026 के तहत बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(2), 109 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी देवा बघेल और देवनाथ बघेल फरार थे। 7 अगस्त को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया।

नकली हार को असली बताकर ग्रामीण से 10 हजार की ठगी

बस्तर। नगरनार थाना क्षेत्र में नकली सोने के हार को असली बताकर ग्रामीण से 10 हजार रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ग्रामीण को करीब पांच लाख रुपये कीमत का सोने का हार बताकर झांसे में लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम, तीन नकली सोने की मालाएं और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस टीम ने तलाश के बाद -मोहन लाल सोलंकी (52 वर्ष), निवासी नेहरू चौक चरौदा, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग- और -मोहन राय (52 वर्ष), निवासी हथनीपारा वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार- को पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

खास खबर

मिनीमाता महतारी जतन योजना से श्रमिक माताओं को मिल रहा आर्थिक संबल

रायपुर। श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर सामने आई है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भिट्टिकला के ढोढ़ीपारा निवासी लीलावती भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। श्रमिक लीलावती के दो बच्चे हैं। बच्चों की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत प्राप्त 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनी है। योजना से मिली राशि का उपयोग वह अपने बच्चों के खान-पान, देखभाल और बेहतर पालन-पोषण में करेंगी।

सभी भूमि धारकों के लिए फार्मर आईडी बनावा अनिवार्य

सक्ती। शासन द्वारा सभी भूमिधारकों (नम्बरदार/सह खातेदार) को एग्रीस्टैक योजना अंतर्गत फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सह खातेदारों एवं सभी खसरों का फार्मर आईडी में एंट्री कराना भी अनिवार्य है। फार्मर आईडी होना एवं सभी खसरों का फार्मर आईडी से लिंक होना पंजीयन के लिए सबसे जरूरी है। फार्मर आईडी किसान की एक डिजिटल पहचान होगी। यह आधार कार्ड की तरह ही एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसमें किसान का व्यक्तिगत विवरण, उसके बैंक खाते की जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण उसका भू-अभिलेख (भुईयां पोर्टल के अनुसार भूमि का विवरण) लिंक होता है। फार्मर आईडी हेतु एक भी खसरा अगर छूटता है तो उसमें किसान धान नहीं बेच पाएंगे। पीएम किसान, फसल बीमा, धान खरीदी, कृषि अनुदान एवं आपदा राहत जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

राखी के धागों के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों तक पहुंचेंगी कवर्धा की बहनों की शुभकामनाएं

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सरहद पर खड़े जवानों की कलाई भले ही इस रक्षाबंधन पर अपने घर की राखी से दूर रहे, लेकिन कवर्धा की बहनों का स्नेह उन तक जरूर पहुंचेगा। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारत माता चौक में आयोजित 'ऑपरेशन रक्षा सूत्र' कार्यक्रम में कवर्धा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों ने अपने हाथों से तैयार राखियां देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए समर्पित कीं।

कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, कवर्धा की माताएं बहने, सेना के जवान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाएं, सखी सेंटर के स्टाफ, जिला महिला सशक्तिकरण के अधिकारी-कर्मचारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं एवं

अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत सेना के जवानों द्वारा भारत माता की आरती के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं ने सैनिक भाइयों को राखियां बांधकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। 'जय जवान' के नारों से पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के भाव से गूंज उठा। खास बात यह रही कि जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों द्वारा तैयार की गई राखियों को एकत्र कर भारतीय सेना तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इन राखियों के साथ कवर्धा की बहनों की शुभकामनाएं और देश की रक्षा में जुटे जवानों के प्रति कृतज्ञता भी सीमा तक पहुंचेगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि राखी केवल एक धागा नहीं है। यह सैनिकों के प्रति विश्वास, सम्मान, आशीर्वाद और कृतज्ञता का भाव है। जो जवान अपने परिवार और अपनों से दूर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए समाज की ओर से भेजा गया यह रक्षा सूत्र उनके मनोबल को और मजबूत करेगा।

केश शिल्पियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, मांगों पर गंभीरता से होगा विचार

सेन समाज सनातन परंपराओं और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने सदियों से भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था, संस्कारों और समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता का इस समाज से होना पूरे सेन समाज के लिए गौरव की बात है।

सेन समाज केवल अपनी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक समाज के प्रत्येक संस्कार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समाज सनातन परंपराओं और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेन समाज के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री एवं

वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि सेन समाज और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उस समय अनेक महत्वपूर्ण पहल की गईं। सैलून संचालन के लिए सेन समाज के लोगों को किट, कुम्हारों को बैटरी चलित चाक और बढ़ई समाज के लोगों को कारपेंट्री किट देने की शुरुआत भी इसी दिशा में की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज की आज की आवश्यकताओं और मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नामकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सेन समाज के विकास और कल्याण के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक हुनर और छोटे-छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण और सामान्य परिवेश में रहकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इससे देश में हुनर और श्रम के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने का काम तेजी से किया गया है।

कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा सेन समाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुनर और प्रतिभा का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। आज उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सेन समाज से विधायक रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन समाज की सेवा और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केश शिल्प कल्याण बोर्ड को युवा नेतृत्व मिला है, निश्चित रूप गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में सेन समाज को आगे बढ़ाने का काम तेजी से होगा।

उपमुख्यमंत्री साव ने अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का किया शुभारम्भ

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के सरकंडा में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का शुभारंभ किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़े। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से राज्य शासन के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसकी शुरुआत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक एवं हितग्राही-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी भी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस अभिनव पहल को आम जनता को समर्पित करते हुए इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी नवाचार, पारदर्शिता एवं सुगम सेवा वितरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राशन कार्डधारी हितग्राही, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के माध्यम से राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी है। हितग्राही मशीन के समक्ष निर्धारित स्थान पर खड़ा होकर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करता है। इसके पश्चात स्क्रीन पर उपलब्ध राशन एवं उसकी मात्रा प्रदर्शित होती है, जिसकी पुष्टि हितग्राही द्वारा की जाती है। हितग्राही अपने खाली बैग अथवा थैले को डिस्पेंसर के नीचे रखकर डिस्पेंस बटन दबाता है। कुछ ही सेकंड में खाद्यान्न स्वत: मशीन से निकलकर बैग में भर जाता है।

चेकमेट एट जशपुर : यहां पहली बार होगा अखिल भारतीय फिडे रेटेड शतरंज महासंग्राम

- 29 अगस्त से 1 सितंबर तक देशभर के खिलाड़ी दिखाएंगे शतरंज का हुनर, 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुर। जशपुर जिले के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जिला प्रशासन एवं खेल विभाग जशपुर तथा जशपुर जिला शतरंज संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिले की पहली अखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता-2026 'चेकमेट एट जशपुर' का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के तत्वावधान में आयोजित होने वाली यह चार दिवसीय प्रतियोगिता 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक जशपुरनगर के पुरानी टोली स्थित कम्युनिटी हॉल में होगी। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेताओं के लिए कुल 2 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है।

कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि जशपुर खेल, शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में निरंतर

आगे बढ़ रहा है। जिले में पहली बार अखिल भारतीय स्तर की फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे जिले के खिलाड़ियों को देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले खिलाड़ी जशपुर की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित होंगे।

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50 हजार रुपये एवं ट्रॉफी, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 30 हजार रुपये एवं ट्रॉफी तथा तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 20 हजार रुपये एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। चौथे स्थान के लिए 11 हजार, पांचवें के लिए 7 हजार, छठे के लिए 5 हजार, सातवें से दसवें स्थान तक प्रत्येक को 3 हजार तथा 11वें से 17वें स्थान तक प्रत्येक खिलाड़ी को 2 हजार रुपये एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कम रेटिंग वाले, अनरेटेड, महिला, वरिष्ठ एवं स्थानीय खिलाड़ियों के लिए भी अलग-अलग पुरस्कार रखे गए हैं। 1650 से कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों, अनरेटेड खिलाड़ियों तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। जशपुर जिले के शीर्ष पांच पुरुष एवं शीर्ष पांच महिला खिलाड़ियों तथा सरगुजा संभाग के शीर्ष पांच पुरुष एवं शीर्ष पांच महिला खिलाड़ियों को भी 2-2 हजार रुपये एवं स्मृति चिह्न से सम्मानित किया जाएगा।

प्रतियोगिता में 15 वर्ष से कम, 13 वर्ष से कम, 11 वर्ष से कम और 9 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए प्रत्येक आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक-बालिका को 2,100 रुपये एवं ट्रॉफी तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1,500 रुपये एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं 17 अगस्त को मॉप-अप दिवस

रायपुर। प्रदेश में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यभर में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी। अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ बच्चों एवं किशोर किशोरियों तक पहुंच कर उन्हें कृमि मुक्ति हेतु एल्बेंडाजोल खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये संक्रमण आमतौर पर खुले में शौच और खराब स्वच्छता के कारण मिट्टी के संक्रमित होने, संक्रमित मिट्टी के संपर्क के बाद बिना साबुन से हाथ धोए भोजन करने, दूषित पानी पीने या दूषित भोजन खाने, मानव मल से दूषित मिट्टी पर नंगे पैर चलने तथा शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ नहीं धोने जैसी परिस्थितियों में फैलते हैं। यदि कोई बच्चा 10 अगस्त को किसी कारणवश दवा नहीं खा पाता है, तो उसे मॉप-अप दिवस 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा एलबेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी।

गुजरात ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर गांधीनगर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म की प्रभावी सहभागिता

- देशभर से पहुंचे पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने राज्य के पर्यटन वैभव को सराहा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास, अधोसंरचना विस्तार और व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं रोमांचक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात के गांधीनगर में 6 से 8 अगस्त तक आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की प्रभावी सहभागिता राज्य की पर्यटन संभावनाओं को देशभर के पर्यटन बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनी है।

देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन प्रचार आयोजनों के माध्यम से पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने वाली संस्था फेयर फेस्ट मीडिया द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण पर्यटन मेले में छत्तीसगढ़ की समृद्ध पर्यटन विरासत को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय एवं सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों,

जलप्रपातों, वन क्षेत्रों और रोमांचक पर्यटन स्थलों की जानकारी देशभर से पहुंचे पर्यटन व्यवसायियों एवं प्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा रही है।

26 पर्यटन व्यवसायियों के साथ प्रभावी सहभागिता

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीकृत 26 ट्रैवल एजेंट एवं होटल व्यवसायियों ने भी सहभागिता की। इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को पर्यटन उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के समक्ष सीधे प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। आगंतुकों को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों, पर्यटन सुविधाओं, भ्रमण की संभावनाओं तथा विभिन्न पर्यटन गंतव्यों की विशेषताओं की जानकारी दी जा रही है।

नए पर्यटन व्यवसायियों ने छत्तीसगढ़ में दिखाई रुचि

छत्तीसगढ़ पवेलियन में बड़ी संख्या में नए ट्रैवल एजेंट, यात्रा संचालक एवं पर्यटन व्यवसायी पहुंचे और राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रति विशेष रुचि व्यक्त की। अनेक नए पर्यटन व्यवसायियों ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीयन कराने में रुचि दिखाई। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन पैकेज एवं यात्रा सुविधाओं के विस्तार के साथ राज्य के पर्यटन स्थलों को व्यापक राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विजन को मिली गति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की विशिष्ट प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन विकास की बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ा रही है। राज्य की जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, ऐतिहासिक धरोहरें, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनें, इसके लिए पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ व्यापक प्रचार-प्रसार और पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ समन्वय पर जोर दिया जा रहा है।

टीटीएफ जैसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में छत्तीसगढ़ की सहभागिता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय पर्यटन बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे छत्तीसगढ़ की पहचान एक समृद्ध और विविधतापूर्ण पर्यटन गंतव्य के रूप में और अधिक मजबूत हो रही है।

आकर्षक छत्तीसगढ़ पवेलियन

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आकर्षक छत्तीसगढ़ पवेलियन तैयार कराया गया। पवेलियन में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत, प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन की विविध संभावनाओं को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है। पवेलियन में पहुंच रहे पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जानकारी के साथ यहां उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं और भ्रमण की संभावनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है।

मल्हार-रतनपुर के समन्वित विकास का बनेगा मास्टर प्लान

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार करें कार्ययोजना

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कहा है कि समय की मांग बदल रही है, इसलिए अधिकारी वर्तमान के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर दूरदर्शी कार्ययोजना बनाएं। विकास कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में विलंब को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करने की बात कही। श्री साव आज बिलासपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। विधायक धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और दिलीप लहरिया भी बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में बिल्हा के बरतोरी से मोहतरा मार्ग पर सड़क के बीच बिजली के खंभे खड़े किए जाने के मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला पंचायत के सीईओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत

करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैठक से अनुपस्थित रहने वाले चार अधिकारियों पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बिल्हा, कोटा और तखतपुर जनपद पंचायत के सीईओ तथा रतनपुर नगर पालिका के सीएमओ को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करते रहने और मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

श्री साव ने कहा कि बिलासपुर शहर में पहली ही बारिश में जलभराव की स्थिति सामने आई है। इससे निपटने के लिए अभी से ऐसी बेहतर और स्थायी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे आने वाले वर्षों में शहरवासियों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सड़कों पर गड्ढे और क्षति की स्थिति बनती है। विभागीय अधिकारी इसकी तैयारी अभी से रखें, ताकि बारिश समाप्त होते ही सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। उन्होंने निर्माण विभागों की अलग से बैठक लेकर कार्यों की विस्तृत समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं।

श्री साव ने मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने गांव स्तर पर लगातार निगरानी रखने तथा मितानिन स्तर तक आवश्यक एवं मूलभूत दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉ. शुभा गरेवाल ने बताया कि कोटा विकासखंड में अब तक मलेरिया के 48 मरीज मिले हैं। इनमें 6 मरीज उपचाररत हैं, जबकि अन्य मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रोटरी क्लब के सहयोग से प्रभावित क्षेत्र में 1500 मच्छरदानियों का वितरण किया जा रहा है।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में पर्याप्त बारिश होने से फसलों की स्थिति अच्छी है। बांधों में भी पर्याप्त जलभराव है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950